[2025] 9 एस.सी.आर. 703 : 2025 आई.एन.एस.सी 1088

महाप्रबंधक (पी), केनरा बैंक

बनाम

गंगनारसिम्हाइया

(सिविल अपील संख्या - 11461/2025)

09 सितम्बर 2025

[जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न उठा कि क्या उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच, औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय को सही ठहराते हुए–जिसमें उत्तरदाता-श्रमिक पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को रद्द कर दिया गया था और उसे बिना पिछले वेतन के, सेवा की निरंतरता के साथ उसके मूल पद पर बहाल करने का निर्देश दिया गया था–उचित थी।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 11ए – श्रम न्यायालय, अधिकरणों की शक्तियाँ - बैंक में तैनात उत्तरदाता-दफ्तरी-सह-कैशियर के विरुद्ध आरोप कि उसने कदाचार/ऋण स्वीकृति में अनियमितता के कारण लाभ उठाया - प्रारंभिक जाँच में उत्तरदाता ने स्वीकार किया कि कुछ ऋण प्रबंधक पर दबाव डालकर और नियंत्रक अधिकारी से बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किए लिए गए थे, तथा उसने बैंक खातों में अनधिकृत प्रविष्टियाँ करने की बात स्वीकार की, जिससे उसने सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की - जाँच में आरोप सिद्ध पाए गए; अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी आरोपों की पुष्टि की गई और उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया - औद्योगिक अधिकरण ने पाया कि जाँच निष्पक्ष थी, तथापि अपने अंतिम अधिनिर्णय में उसने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह उत्तरदाता को बिना पिछले वेतन के सेवा में बहाल करे - उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम अधिनिर्णय को यथावत रखा गया

अभिनिर्धारित: ट्रिब्यूनल और साथ ही हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश मान्य नहीं हैं - ट्रिब्यूनल और साथ ही हाई कोर्ट, अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहे - हाई कोर्ट ने अपने अप्रासंगिक कारण जोड़ते हुए, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर दी; उसने इस तरह से काम किया मानो वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा हो। वह इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा कि विभागीय कार्यवाही में, साक्ष्य के वे कड़े नियम, जो न्यायिक कार्यवाही में लागू होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, और कदाचार का आरोप केवल 'संभावनाओं की प्रबलता' (preponderance of probabilities) के आधार पर ही सिद्ध किया जाना चाहिए - जांच

अधिकारी और साथ ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाता पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं - अपीलीय प्राधिकारी ने भी साक्ष्यों की पुनः जांच की और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की - उनके आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि ये आदेश बिना किसी साक्ष्य के आधारित थे, या कि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में ये विकृत (perverse) थे - ट्रिब्यूनल ने एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि इस बात की अत्यधिक संभावना है कि आरोप-पत्र में कथित अनियमितताएं प्रबंधक द्वारा उत्तरदाता के कहने पर की गई थीं, और वह उस अनियमित ऋण स्वीकृति का प्रत्यक्ष लाभार्थी था, उसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दंड आदेश में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया - किसी कर्मचारी की सेवा से 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का अर्थ यह नहीं है कि वह कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार नहीं है; इन लाभों से केवल 'सेवा से बर्खास्तगी' के मामले में ही वंचित किया जा सकता है - ट्रिब्यूनल और साथ ही हाई कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है - तथापि, चूंकि उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है, इसलिए वह कानून के अनुसार ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन संबंधी लाभों का हकदार है। [पैरा 30, 34, 39-41]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकारी) एवं अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव **[2021] 1 एस.सी.आर 51 : (2021) 2 एस.सी.सी 612;** स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आर.सी. श्रीवास्तव **(2021) 19 एस.सी.सी 281;** इंडियन ओवरसीज बैंक एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव **[2022] 1 एस.सी.आर 246** : **(2022) 3 एस.सी.सी 803;** बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारतीय संघ एवं अन्य **[1995] अनुपूरक 4 एस.सी.आर 644 : (1995) 6 एस.सी.सी 749;** राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम हीम सिंह **[2020] 13 एस.सी.आर951 : (2021) 12 एस.सी.सी 569;** स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेमी चंद नलवाया **[2011] 3 एस.सी.आर 589 : (2011) 4 एस.सी.सी 584** - **संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947)

प्रमुख शब्दों की सूची

अनिवार्य सेवानिवृत्ति; सेवा बहाली; गंभीर अनियमितताएं; बैंक खातों में अनधिकृत प्रविष्टियां; सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़; प्रबंधक पर दबाव डालना; अनुशासनात्मक मामलों में

महाप्रबंधक (पी), केनरा बैंक बनाम गंगनारसिम्हाइया

न्यायिक समीक्षा; अनुशासनात्मक जांच; नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत; सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच; अनुशासनात्मक प्राधिकारी; साक्ष्य के कठोर नियम; विभागीय कार्यवाही; संभावनाओं की प्रबलता; सेवानिवृत्ति लाभ; सेवा से बर्खास्तगी; पेंशन संबंधी लाभ; बिना पिछले वेतन के सेवा की निरंतरता; निलंबन।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 11461/2025

रिट याचिका सं०. 1857/2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 12.08.2022 के निर्णय और आदेश से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण: राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, दीपांजल चौधरी, दिनेश शर्मा, सुश्री लिकिवी जाखालू।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण: साजू जैकब, तीर्थगौड़ा एन.एम., प्रीयोशी भट्टाचार्जी, सेंथिल कुमार, चांद कुरेशी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

विजय बिश्नोई, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई |
2. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1857/2020 (श्रम/अवशिष्ट) में दिनांक 12.08.2022 को पारित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, इसके द्वारा, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" कहा जाएगा) द्वारा सिविल पुनरीक्षण सं० 138/2007 में दिनांक 25.09.2019 को पारित अधिनिर्णय की पुष्टि की; जिसमें उत्तरदाता पर अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को रद्द करते हुए, उसे बिना किसी पिछले वेतन (back wages) के, सेवा की निरंतरता के साथ उसके मूल पद पर बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

संक्षिप्त तथ्य

3. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता 17.10.1990 को अपीलकर्ता-बैंक की सेवा में दैनिक वेतन भोगी उप-कर्मचारी के रूप में शामिल हुआ। उनकी सेवा 18.07.1992 को सब-स्टाफ़ लीडर के रूप में दफ़्तरी-सह-कैश चपरासी के पद पर स्थायी कर दी गई। तत्पश्चात, उत्तरदाता को 11.11.1997 से 01.08.2004 तक वी.जी. डोड्डी शाखा में तैनात किया गया। इसके बाद, 02.08.2004 को उसे बोम्मासंद्रा शाखा में तैनात किया गया।

4. वी.जी. डोड्डी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक, श्री एच.एन. रमेश ने 06.08.2004 को एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वी.जी. डोड्डी शाखा कार्यालय में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था उस समय जब उत्तरदाता और अन्य कर्मचारी वहाँ तैनात थे।

5. उक्त अनियमितताओं के संबंध में एक प्रारंभिक जाँच की गई, और इस जाँच के दौरान, 24.07.2004 को उत्तरदाता ने यह स्वीकार किया कि उसकी पत्नी को कुछ ऋण दिए गए थे; ये ऋण प्रबंधक पर दबाव डालकर प्राप्त किए गए थे और इसके लिए नियंत्रक अधिकारी से कोई स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। उत्तरदाता ने यह भी स्वीकार किया कि उसने श्री रामकृष्णैया और उनके पिता, श्री कंबैया के बैंक खातों में अनधिकृत प्रविष्टियाँ कीं, जिसके द्वारा उसने सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की।

6. इसके बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के विचार के चलते 19.08.2004 को उत्तरदाता को निलंबित कर दिया गया, और तत्पश्चात, आरोपों के संबंध में उत्तरदाता को दिनांक 28.04.2005 का एक आरोप-पत्र जारी किया गया। आसान संदर्भ के लिए, आरोप-पत्र को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

आरोप

- बोम्मासंद्रा शाखा में 02.08.2004 को शामिल होने से पहले, आप 11.11.1997 से 01.00.2004 तक हमारी वी.जी.डोड्डी शाखा में कार्यरत थे, और 19.08.2004 को आपको निलंबित कर दिया गया था।
- हमारी वी.जी.डोड्डी शाखा के 'एडवांसेज़ पोर्टफोलियो' में गंभीर विसंगतियाँ पाई गईं, और इस मामले में की गई जाँच से आपकी ओर से निम्नलिखित अनियमितताएँ/धोखाधड़ी के कृत्य सामने आए हैं:
- एफजीसी 1/2000 के तहत, दिनांक 03.04.2000 को श्री कंबैया को 25,000/- रुपये।

- दिनांक 03.04.2000 को, श्री कंबैया पिता - श्री रंगैया, स्थान - नायकनपाल्या, मगदी तालुक – जो आपके पिता हैं – को 25,000 रुपये का एफजीसी 1/2000 स्वीकृत किया गया है।
- दिनांक 01.03.2000 को, तत्कालीन मैनेजर श्री आर. आर. हूवर ने श्री कंबैया के एस.बी खाता संख्या 519 में 10,000/- रुपये का अस्थायी ओवरड्राफ्ट मंज़ूर किया था। फिर 24.03.2000 को, आपने अपने पिता के खाते में 25,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया और मैनेजर को सूचित किया कि आपके पिता ऋण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए शाखा में आएंगे। आपके कहने पर, श्री आर. आर. हूवर ने एफजीसी खाते को डेबिट करके और श्री कंबैया के एस.बी खाता संख्या 519 को क्रेडिट करके डेबिट और क्रेडिट पर्चियां तैयार कीं। एफजीसी ऋण देने वाली पर्चियां बिना ऋण-पत्र तैयार किए ही बना दी गईं, क्योंकि श्री कंबैया ऋण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वयं शाखा में उपस्थित नहीं हुए थे।
- आपने श्री कंबैया के एस.बी 519 खाते में क्रेडिट स्लिप पोस्ट कीं और उसी दिन, यानी 24.03.2000 को, उनके एस.बी खाते से 15,000 रुपये निकाल लिए। अपने पिता के एफजीसी लोन में हुए अनधिकृत डेबिट को ठीक करने के लिए, आपने अगले दिन, यानी 25.03.2000 को, मैनेजर की जानकारी के बिना, खाते से डेबिट करने के लिए कोई स्लिप तैयार किए बिना, और कोई संबंधित क्रेडिट दिखाए बिना, श्री रामकृष्णैया के एस.बी खाता 1550 से अनधिकृत रूप से राशि डेबिट कर दी। आपने यह राशि केवल लेजर शीट में डेबिट की, और सहायक शीट में कोई प्रविष्टि नहीं की।
- आपने इस अनाधिकृत लेन-देन की जानकारी मैनेजर को 31.03.2000 को ही दी। इसके बाद, श्री आर. आर. हूवर ने उसी दिन श्री रामकृष्णैया के एस.बी 1550 खाते को डेबिट करके और एफजीसी सहायक खाते को क्रेडिट करके इन स्लिप्स को पास कर दिया। ऐसा करने से, 24.03.2000 को श्री कंबैया की अनुपस्थिति में दिए गए एफजीसी ऋण से संबंधित एंट्री उलट गई, और श्री रामकृष्णैया के एस.बी 1550 खाते में किया गया अनाधिकृत डेबिट बकाया रह गया। इसके बाद, एस.बी 1550 में हुए अनाधिकृत डेबिट और एफजीसी खाते में किए गए क्रेडिट के लेन-देन को ठीक करने के लिए, श्री आर. आर. हूवर ने 03.04.2000 को जल्दबाजी में श्री कंबैया को एफजीसी 1/2000 के तहत 25,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया; इसके लिए उन्होंने विधिवत ऋण-पत्र प्राप्त किए और ऋण की राशि को श्री रामकृष्णैया के एस.बी 1550 खाते

में जमा (क्रेडिट) कर दिया, जिससे वह अनाधिकृत डेबिट पुनः क्रेडिट हो गया। इस लेन-देन से संबंधित डेबिट स्लिप की एंट्री आपने ही की थी। आपने अपने निजी लाभ के लिए, जान-बूझकर अपने पिता और श्री रामकृष्णैया के खातों में ये अनाधिकृत एंट्रीज़ की थीं।

- शाखा के पार्ट टाइम एम्प्लोयी. श्री चेन्नवेंकटैया ने 25.03.2000 को एसबी बैलेंसिंग बुक में ₹25,000/- की डेबिट एंट्री से पहले ₹3,00,196/- का बैलेंस निकाला था। आपने जान-बूझकर बैलेंसिंग बुक में फेरबदल किया और बैलेंसिंग बुक को मिलाने के लिए ₹2,75,196/- की राशि को बदल दिया। आपने एसबी कंट्रोल रजिस्टर और लेजर सब्सिडियरी में भी फेरबदल किया, ताकि खातों का मिलान हो सके; यह बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ और उन्हें गलत तरीके से पेश करने के बराबर है।
- श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 खाते में हुई इस अनाधिकृत डेबिट प्रविष्टि को छिपाने के उद्देश्य से, आपने उनकी पासबुक को अपडेट करते समय जान-बूझकर डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को छोड़ दिया। आपने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आपने पासबुक में इन प्रविष्टियों को जान-बूझकर छोड़ा था।
- श्री रामकृष्णैया का इस लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं था; मैनेजर ने यह ऋण आपकी ही गुज़ारिश पर और आपकी ही ज़ोर-ज़बरदस्ती के कारण दिया था।
- श्री आर. आर. हूवर, मैनेजर ने श्रीमती सुवर्ममा (जो आपकी पत्नी हैं) के एसबी खाता संख्या 2450 में, 16.4.99 से 23.5.2000 की अवधि के दौरान 8 बार अस्थायी ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी थी, जिनकी कुल राशि 55,857/- रुपये थी। इसके अलावा, उन्हें 20,000/- रुपये का डीपीएन आरटी 22/09, 25,000/- रुपये का डीपीएन आरटी 31/99 और 25,000/- रुपये का एएलएस 15/03 भी स्वीकृत किया गया था। साथ ही, आपके पिता श्री कंबैया को एएलएस 10/02 के तहत 25,000/- रुपये और एएलजीएल 98/03 के तहत 25,000/- रुपये के अतिरिक्त ऋण भी स्वीकृत किए गए थे, जिनके लिए कंट्रोलिंग ऑफिस की सहमति नहीं ली गई थी।
- आपने निजी लाभ के लिए धन जुटाने हेतु एसबी खाता 1550 में अनधिकृत रूप से डेबिट किए हैं। आपने निजी लाभ के लिए अपने परिवार के सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रबंधक पर दबाव डाला है। आपने अनधिकृत डेबिट

के कारण खातों को धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से संतुलित रखने के लिए, बैलेंसिंग बुक, की रजिस्टर और एसबी सहायक शीटों में फेरबदल करके बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है।

- हमारे स्टाफ अनुभाग (अधिकारी), सर्किल कार्यालय, बैंगलोर ने अपने पत्र सं० बीएलसी/एसएसओ/7023/ईपी दिनांक 04.10.2004 के माध्यम से, इस मामले पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा था। आपके द्वारा दिनांक 02.11.2004 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया उत्तर न तो विश्वसनीय है और न ही संतोषजनक।
- "आपने अपने उपरोक्त कार्यों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यंत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और तत्परता के साथ करने में असफलता दिखाई है; और इस प्रकार, आपने 'केनरा बैंक सेवा संहिता' के अध्याय XI, विनियम 2(ए), (i) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा एक 'घोर कदाचार' (Gross Misconduct) किया है।"

7. 07.06.2005 को, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक जाँच अधिकारी और एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया। जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी होने के बाद 09.01.2006 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरदाता पर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

8. जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई, और इसके जवाब में उत्तरदाता ने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए यह आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष नहीं थी, क्योंकि दो प्रासंगिक गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी।

9. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता को दिनांक 10.03.2006 का "कारण बताओ नोटिस" जारी किया, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड का प्रस्ताव किया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। अंततः दिनांक 15.03.2006 को, जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित कर दिया।

10. व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसने दिनांक 22.11.2006 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकृत कर दिया।

11. इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष उठाए गए विवाद के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अधिकरण को एक संदर्भ भेजा, जिसके संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

> "क्या केनरा बैंक के प्रबंधन द्वारा श्री गंगानरसिम्हाइया पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जो दंड लगाया गया है, वह वैध और उचित है? यदि नहीं, तो कर्मचारी किस प्रकार की राहत का हकदार है?"

12. ट्रिब्यूनल ने एक प्रारंभिक मुद्दा तय किया कि क्या उत्तरदाता के विरुद्ध की गई आंतरिक जाँच निष्पक्ष एवं उचित है अथवा नहीं? उत्तरदाता की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए:

- कुछ प्रमुख गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है और उन्हें कुछ प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- डिपार्टमेंटल गवाहों से पूछताछ करने के लिए पूरा मौका नहीं दिया गया; और
- जांच की कार्यवाही कन्नड़ भाषा में न होकर अंग्रेजी भाषा में की गई, जिससे उत्तरदाता और उसके बचाव प्रतिनिधि को अपना बचाव प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असुविधा हुई।

ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाता के उपरोक्त तर्कों पर विचार करने के बाद, और साथ ही अपीलकर्ता-बैंक के पक्ष पर भी विचार करते हुए, दिनांक 17.05.2013 के आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला था कि जाँच निष्पक्ष थी। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 17.05.2013 के आदेश का मुख्य भाग यहाँ नीचे दिया गया है:-

> "....अतः, मुझे ऐसा कहने का कोई आधार नहीं मिलता कि सीएसई या उनके बचाव प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का उचित और सही अवसर नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, इस मुद्दे का उत्तर 'सकारात्मक' देते हुए और यह मानते हुए कि II पक्ष द्वारा I पक्ष के विरुद्ध की गई 'घरेलू जाँच' (Domestic Enquiry) उचित और सही थी, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:"
>
> **आदेश**
>
> प्रारंभिक मुद्दे का उत्तर 'सकारात्मक' रूप में दिया जाता है, जिसमें यह माना गया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध की गई घरेलू जाँच निष्पक्ष और उचित है...

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 17.05.2013 को पारित उक्त आदेश को उत्तरदाता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, और इस प्रकार, वह अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

13. ट्रिब्यूनल ने दिनांक 25.09.2019 के आदेश के माध्यम से अंतिम अधिनिर्णय पारित किया और संदर्भ का उत्तर प्रत्यर्थी के पक्ष में दिया, तथा अपीलार्थी को निर्देश दिया कि वह कामगार को बिना पिछले वेतन के, सेवा की निरंतरता के साथ उसके मूल पद पर पुनः बहाल करे।

14. इसके बाद, अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 25.09.2019 को पारित अंतिम अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित रिट याचिका संख्या 1857/2020 (श्रम/अवशिष्ट) प्रस्तुत की।

15. हाई कोर्ट ने दिनांक 12.08.2022 के विवादित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड को बरकरार रखा।

<u>पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया है। यह दलील दी गई है कि, यद्यपि ट्रिब्यूनल ने दिनांक 17.05.2013 के आदेश के माध्यम से यह माना था कि उत्तरदाता के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक जाँच निष्पक्ष और उचित थी, फिर भी उसने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया और दंडादेश में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया।

17. विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि प्रबंधन ने उत्तरदाता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया, गलत और कानून के विपरीत है। यह तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान 19 दस्तावेज़ पेश किए गए थे, और जांच अधिकारी के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने भी उन दस्तावेज़ों पर विस्तार से विचार किया, इस तथ्य के बावजूद कि प्रारंभिक जांच के दौरान उत्तरदाता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया था, उनकी प्रतियां उत्तरदाता को दी गई थीं और उसे गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दंड आदेश में हस्तक्षेप करके घोर त्रुटि की है, और उच्च न्यायालय ने भी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करके गलती की है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों केवल इस तथ्य से प्रभावित थे कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरदाता ही उन प्रविष्टियों का कर्ता था, जिनके माध्यम से उत्तरदाता के पिता श्री रामकृष्णैया, श्री कंबैया और बैंक के अन्य ग्राहकों के बैंक/ऋण खातों में कुछ अनियमित/अवैध लेनदेन किए गए थे। आगे यह तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने यह टिप्पणी करने के बावजूद कि यह अत्यधिक संभव है कि उत्तरदाता के कहने पर प्रबंधक ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के अनुसार अनियमितताएं कीं, और यह भी टिप्पणी करने के बावजूद कि उत्तरदाता ही उस कदाचार/ऋण स्वीकृति का लाभार्थी था, दंड आदेश में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया है। यह तर्क दिया गया है कि कानून की यह एक स्थापित स्थिति है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों की जांच 'संभावनाओं की प्रबलता' (preponderance of probabilities) के सिद्धांत पर की जानी चाहिए।

18. अपीलकर्ता के वकील ने आगे यह तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने यह कहने में गलती की है कि उत्तरदाता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा बहुत कठोर और असंगत है, जबकि उसने यह माना था कि उत्तरदाता को कदाचार/गलत तरीके से लोन मंज़ूर करने के कारण फ़ायदा हुआ था। ट्रिब्यूनल ने यह भी गलत कहा है कि यदि उत्तरदाता को सेवा में बहाल किया जाता है, तभी उसे सेवानिवृत्ति के लाभ मिलेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने पर भी उसे सेवानिवृत्ति के लाभों का अधिकार होगा, क्योंकि यह सेवा से बर्खास्तगी का मामला नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि उस समय वी.जी. डोड्डी शाखा में काम करने वाले अन्य कर्मचारी, यानी श्री आर. आर. हूवर और श्री एन. गोविंदा राजु के ख़िलाफ़ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, और चूंकि उनके ख़िलाफ़ आरोप सिद्ध हो गए थे, इसलिए उन पर भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा लागू की गई थी। उन्होंने इस सज़ा को चुनौती दी थी, जिसे अपीलीय और समीक्षा प्राधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था; इसके बाद, उन्होंने किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई और चुनौती नहीं दी, और इसलिए, उन पर लागू की गई सज़ा अंतिम मानी गई।

19. अपीलकर्ता के वकील ने आगे यह तर्क दिया है कि ग्राहक बैंकों पर भरोसा करते हैं और इस विश्वास के साथ अपना पैसा जमा करते हैं कि उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में, यदि बैंक का कोई कर्मचारी ग्राहकों के खातों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की गलत प्रथाओं या अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है, तो आम जनता का बैंकिंग प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता अजनबियों के बैंक खातों में अनधिकृत लेनदेन करने में लिप्त पाया गया था, और साथ ही वह अपने पिता और अपनी पत्नी के खातों में भी अनियमित लेनदेन करने में शामिल था; इसलिए, यह उचित नहीं है कि ऐसा कर्मचारी बैंकिंग प्रणाली में बना रहे। उत्तरदाता द्वारा की गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप नियोक्ता का विश्वास समाप्त हो गया, और ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदाता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना बिल्कुल सही था।

20. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित उन निर्णयों पर भरोसा किया है जो **डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकारी) एवं अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2021) 2 एसएससी 612** में, **स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आर.सी. श्रीवास्तव (2021) 19 एसएससी 281** में, **और इंडियन ओवरसीज बैंक एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव (2022) 3 एसएससी 803** में रिपोर्ट किए गए हैं।

21. इसके विपरीत, उत्तरदाता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अपील का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करने में कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं किया है, क्योंकि अपीलकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि रिकॉर्ड में अनधिकृत प्रविष्टियाँ और छेड़छाड़ उत्तरदाता द्वारा की गई थी। उत्तरदाता के विद्वान वकील ने आगे यह भी तर्क दिया कि जाँच अधिकारी दो महत्वपूर्ण गवाहों, यानी श्री रामकृष्णैया और श्री आर.आर. हूवर से पूछताछ करने में भी विफल रहे, और जाँच अधिकारी ने यह सत्यापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की राय भी नहीं ली कि क्या विवादित प्रविष्टियाँ उत्तरदाता की लिखावट में की गई थीं।

22. उत्तरदाता के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि उत्तरदाता द्वारा अपराध स्वीकार करने वाले जिन बयानों पर अपीलकर्ता भरोसा कर रहा है, वे स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, बल्कि उन्हें धमकी और ज़बरदस्ती के तहत लिया गया था। यह दावा किया गया है कि उत्तरदाता ने केवल 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, और यह समझना मुश्किल है कि वह, जो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है, उसने अपने पिता या किसी अन्य ग्राहक के बैंक खातों में प्रविष्टियाँ की होंगी। यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में, उत्तरदाता के पिता और अन्य ग्राहकों के ऋण/बैंक खातों में हुई समस्त अनियमितताएँ उस समय के बैंक प्रबंधक द्वारा की गई थीं, और उत्तरदाता को झूठा फँसाया गया है।

23. आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता-बैंक ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि प्रत्यर्थी कथित कदाचार में सीधे तौर पर शामिल था; अतः, अधिकरण ने यह सही निर्णय दिया है कि प्रत्यर्थी पर अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अत्यधिक कठोर और असंगत है।

24. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

25. उत्तरदाता पर यह आरोप है कि जब वह अपीलकर्ता-बैंक की वी.जी. डोड्डी शाखा में सब-स्टाफ़ के तौर पर तैनात था, तो उसने कुछ अनियमितताएँ की थीं। इसी के चलते, उत्तरदाता को 19.08.2004 को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद 28.04.2005 को उसे एक आरोप-पत्र सौंपा गया। जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरदाता पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं और इस प्रकार वह कदाचार का दोषी है। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति उत्तरदाता को दी गई और

उससे स्पष्टीकरण माँगा गया, जिसके जवाब में उसने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने और उसके बचाव पर विचार करने के बाद जाँच रिपोर्ट से सहमति जताई और दिनांक 15.03.2006 के आदेश के माध्यम से उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित वह आदेश, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है, नीचे दिया गया है:

- मैंने आरोप-पत्र, जाँच की कार्यवाही, संबंधित दस्तावेज़, जाँच अधिकारी के निष्कर्षों तथा सीएसई के प्रस्तुतीकरणों का अवलोकन किया है।
- श्री गंगानरसिम्हैय्या 11.11.97 से 01.08.2004 तक हमारी वी.जी. डोड्डी शाखा में कार्यरत थे; इसके बाद 02.08.04 को उन्होंने बोम्मासंद्रा शाखा में कार्यभार ग्रहण किया, और 19.08.04 से उन्हें निलंबित कर दिया गया।
- वी.जी. डोड्डी शाखा के 'एडवांसेज़ पोर्टफोलियो' में गंभीर विसंगतियाँ पाई गईं, और इस मामले में की गई जाँच से उनकी ओर से और भी अधिक अनियमितताओं/धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का पता चला।
- आरोप ऊपर उल्लिखित आरोप-पत्र में विस्तारपूर्वक सूचीबद्ध हैं, जिसे इस आदेश का अभिन्न अंग माना जाएगा।
- जांच किए जाने पर, श्री गंगानरसिम्हाइया को ई.ओ की जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का 'दोषी' पाया गया; यह रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई थी, और इसके जवाब में सीएसई ने अपने दिनांक 28.01.06 के पत्र के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।
- अभिलेखों के अवलोकन पर, मैं निम्नलिखित बातें पाता हूँ:
- जांच के दौरान, 19 दस्तावेज़ों को 'मैनेजमेंट एग्ज़िबिट्स' के रूप में प्रस्तुत किया गया और दो गवाहों की जांच की गई। बचाव पक्ष/सीएसई की ओर से एक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया और कोई भी गवाह पेश नहीं किया गया।
- श्री एच. एन. रमेश, जो प्रबंधक और जांच अधिकारी थे, की एमडब्लू-1 के रूप में जांच की गई। उन्होंने दस्तावेज़ एमएक्स-1 से एमएक्स-16 की पहचान की है। एमएक्स-1, जिसकी सामग्री की पुष्टि एमडब्लू-1 द्वारा की गई थी, से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:
- 03.05.2000 को, एफजीसी से 25,000/- रुपये श्री कंबैया को दिए गए, जो आरोप-पत्रित कर्मचारी के पिता हैं। एफजीसी 1/2000 के लिए एक डेबिट स्लिप तैयार की गई थी और श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 के लिए एक क्रेडिट स्लिप तैयार

की गई थी। एसबी 1550 की लेजर शीट में, 25.03.2000 को एफजीसी 1/2000 के नाम पर 25,000/- रुपये का डेबिट दर्ज है, और 03.04.2000 को एफजीसी द्वारा 25,000/- रुपये का क्रेडिट किया गया है। ये लेजर प्रविष्टियाँ सीएसई की लिखावट में हैं। 25.03.2000 के स्लिप बंडल में कोई "संबंधित डेबिट और क्रेडिट स्लिप" नहीं है। 31.03.2000 के स्लिप बंडल में, 25,000/- रुपये की एक डेबिट स्लिप है, जिसमें श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 खाते से एफजीसी 1/2000 के लिए राशि डेबिट की गई है, और एफजीसी 1/2000 खाते में जमा करने के लिए उतनी ही राशि की एक क्रेडिट स्लिप भी है। डेबिट स्लिप पर लेजर फोलियो नंबर 78.12 अंकित है, जिस पर सीएसई के हस्ताक्षर हैं, और यह स्लिप मैनेजर श्री रॉबर्ट आर. हूवर द्वारा जारी की गई थी। एसबी लेजर का बैलेंस पीटीई श्री चन्नवेंकटैया द्वारा निकाला गया था। कुल बैलेंस को बदलकर 2,75,196/- रुपये कर दिया गया था, और बैलेंस का मिलान हो गया था। एसबी बैलेंसिंग बुक में किए गए ये बदलाव, जैसा कि स्वीकार किया गया है, सीएसई की ही लिखावट में हैं। एसबी की-रजिस्टर भी सीएसई की ही लिखावट में है। अंतिम कुल योग को 'व्हाइट फ्लूइड' का उपयोग करके बदला गया था, और उस पर सीएसई ने अपने हस्ताक्षर किए थे। सीएसई ने यह स्वीकार किया है कि उसने 31.03.2000 को मैनेजर की जानकारी के बिना ही श्री रामकृष्णैया के खाते से राशि डेबिट की थी। मैनेजर श्री रॉबर्ट आर. हूवर को 25.03.2000 को एसबी खाता संख्या 1550 से 25,000/- रुपये की राशि डेबिट किए जाने, तथा एसबी की-रजिस्टर और एसबी बैलेंसिंग बुक में किए गए बदलावों के बारे में पता चला। सीएसई ने दया की गुहार लगाई, और इसी कारण मैनेजर ने केंद्रीय कार्यालय को इस बारे में कोई पत्र नहीं लिखा। श्री रॉबर्ट आर. हूवर ने, उपरोक्त लेनदेन को ठीक करने के उद्देश्य से, 31.03.2000 को ट्रांसफर स्लिपें तैयार कीं, जिनके माध्यम से एसबी 1550 खाते से राशि डेबिट करके उसे एफजीसी हैड (head) में जमा किया गया। सीएसई ने एसबी 1550 की पासबुक में प्रविष्टियाँ करते समय जान-बूझकर उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों को छोड़ दिया था, और सीएसई ने लिखित रूप में इस बात को स्वीकार भी किया है। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

- सीएसई ने 24.07.2004 के अपने बयान में यह स्वीकार किया कि उसने 19.12.1997 को सीएसई की पत्नी श्रीमती सुवर्णम्मा के नाम पर एसबी 2450 खाता खुलवाया था। वह न तो कोई नौकरी करती हैं और न ही कोई व्यवसाय, लेकिन वह सिलाई-कढाई सीखने की क्लास में जाती हैं। उन्होंने इस खाते में अस्थायी ओवरड्राफ्ट लिए थे और उन्हें चुका भी दिया था। सीएसई ने संबंधित पर्चियाँ अपनी स्वयं की लिखावट में पोस्ट की हैं। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

- सीएसई ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर 20,000/- रुपये का डीपीएनारटी 22/98, 25,000/- रुपये का डीपीएनारटी 31/99 और 25,000/- रुपये का एएलएस 15/2003 लिया था। सीएसई ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने एफजीसी 1/2000 की पर्चियों को एसबी 519 और एसबी 1550 की एसबी लेजर शीट में दर्ज किया था। यह भी कि श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 और उनके पिता के एफजीसी 1/2000 के बीच कोई संबंध नहीं है। एसबी 1550 से 25,000/- रुपये डेबिट किए जाने की जानकारी श्री रामकृष्णैया को नहीं दी गई थी। सीएसई ने यह भी स्वीकार किया कि श्री रामकृष्णैया 25.03.20010 और 03.04.2000 से अपनी ही राशि से वंचित हैं। सीएसई ने अपने 28.07.2004 के बयान में यह स्वीकार किया है कि उसने जान-बूझकर एफजीसी 1/2000 से संबंधित विवरणों को छोड़ते हुए पास बुक संख्या 1550 में प्रविष्टियाँ की थीं। सीएसई ने यह स्वीकार किया है कि उसने एसबी 2959 की एसबी लेजर शीट संख्या 549518 में प्रविष्टियाँ की थीं, जो श्री जॉर्ज जोसेफ से संबंधित है।
- एमएक्स-4 के जरिए यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि श्री रॉबर्ट आर. हूवर ने सीएसई के कहने पर, श्री कंबैया (एसबी 519) के खाते में 10,000/- रुपये का अस्थायी ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। इस अस्थायी ओवरड्राफ्ट को क्लियर करने के लिए, उन्होंने एफजीसी 1/2000 की एक डेबिट स्लिप तैयार की। हालाँकि, सीएसई ने एसबी खाता 1550 से रकम डेबिट कर दी। श्री रॉबर्ट आर. हूवर ने यह भी बताया कि सीएसई ने एसबी बैलेंसिंग और एसबी कंट्रोल रजिस्टर में लिखे अंकों में बदलाव किया था। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**
- एमएक्स -7, 8, 13 और एमएक्स -15 के ज़रिए यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि 25.03.2000 को एसबी 1550 लेजर शीट में की गई 25,000/- रुपये की डेबिट एंट्री, उस दिन की एसबी सब्सिडियरी शीट में दिखाई नहीं दे रही है। एसबी पास बुक नंबर 1550 में 25.03.2000 की 25,000/- रुपये की डेबिट एंट्री और 03.04.2000 की 25,000/- रुपये की क्रेडिट एंट्री नहीं दिखाई गई है, जो एसबी 1550 की लेजर शीट में की गई थीं। 31.03.2000 के एसबी डेली कंट्रोल रजिस्टर में, लेजर नंबर 2 से जुड़ी डेबिट एंट्री को 68/- रुपये से बदलकर 25,068/- रुपये कर दिया गया है और स्लिप की संख्या को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। लेकिन स्लिप की कुल संख्या 8 ही रखी गई है, जबकि असल में यह 9 होनी चाहिए थी। लेजर नंबर 2 का क्लोजिंग बैलेंस और ग्रैंड टोटल भी बदल दिया गया है। सीएसई ने 24.07.2004 को दिए अपने बयान में इन बदलावों को करने की बात स्वीकार की है।
- एमडब्लू 1 के बयान के आधार पर (एमएक्स 16 पर आधारित है) यह बात भी रिकॉर्ड पर लाई गई है कि चार्जशीटेड कर्मचारी की पत्नी श्रीमती सुवम्मा के

एसबी खाता संख्या 2450 में 16.04.99, 05.10.99, 11.10.99, 23.10.99, 08.11.99, 01.03.2000 और 03.04.2000 को अस्थायी ओवरड्राफ्ट s की अनुमति दी गई थी।

- एमडब्लू 2 श्री चन्नवेंकटैया पीटीई ने 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार एसबी लेजर नंबर से बैलेंस निकाला था; उन्होंने पुष्टि की है कि एसबी 1550 में उनके द्वारा निकाला गया बैलेंस 3,00,196 रुपये था, जबकि बदली हुई रकम 2,75,196 रुपये थी। बैलेंस का मिलान नहीं हो पाया था और बैलेंस में बदलाव उनके द्वारा नहीं किया गया था; उन्होंने तो बस एक रफ शीट पर कुल योग निकाला था, क्योंकि उसका मिलान नहीं हो रहा था।
- एसबी खाता सं० 519 में 1998 और 1999 के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ था। 01.03.2000 को एक निष्क्रिय खाते पर अस्थायी ओवरड्राफ़्ट की अनुमति दी गई थी, जो कि ब्रांच मैनेजर का कोई नियमित काम नहीं है। श्री कंबैया सीएसई के पिता हैं, और इसलिए, दी गई अस्थायी ओवरड्राफ़्ट को सीएसई पर दबाव बनाने के अलावा किसी और मकसद से सही नहीं ठहराया जा सकता। अस्थायी ओवरड्राफ़्ट 15 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया रहा और 24.03.2000 को Rs.25,000/- की एक एंट्री पोस्ट करके इसे एडजस्ट किया गया, जिसका विवरण "एफजीसी 1/2000" था। यह एंट्री सीएसई द्वारा पोस्ट की गई थी, हालाँकि मैनेजर के लिए यह एंट्री पढ़ने लायक नहीं थी। एफजीसी 1/2000 को 03.04.2000 को मंज़ूरी दी गई थी, और सीएसई, जिसने 24.03.2000 को स्लिप्स पोस्ट की थीं, वह अपनी अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता; सीएसई को इस बारे में पूरी जानकारी थी और उसने जान-बूझकर मैनेजर की मिलीभगत से ये स्लिप्स पोस्ट की थीं।
- एमडब्लू 1 ने बताया कि सीएसई ने 01.03.2000 को मैनेजर से संपर्क किया और उन पर अपने पिता के खाते में 10,000/- रुपये का अस्थायी ओवरड्राफ्ट देने का दबाव डाला, जिसे उन्होंने 7 दिनों के भीतर चुकाने की अनुमति दी थी। 24.03.2000 को, सीएसई ने फिर से मैनेजर से संपर्क किया और 25,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी, और उन पर एफजीसी और एसबी खाते के लिए 25,000/- रुपये की डेबिट और क्रेडिट पर्ची तैयार करने का दबाव डाला; उसने कहा कि उसके पिता उस दिन ऋण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए शाखा में आएंगे। श्री कंबैया वहां नहीं आए, लेकिन राशि निकाल ली गई, और बाद में 25.03.2000 को, मैनेजर की जानकारी के बिना, श्री रामकृष्णैया के एसबी खाता संख्या 1550 से 25,000/- रुपये डेबिट कर दिए गए। पर्चियों के बंडलों में इससे संबंधित कोई डेबिट या क्रेडिट पर्ची मौजूद नहीं है। 31.03.2000 को, श्री रामकृष्णैया के एसबी खाता संख्या 1550 से 25,000/-

- रुपये डेबिट करने की एक पर्ची मिली, जिस पर लेजर फोलियो संख्या 7812 अंकित है और सीएसई के हस्ताक्षर (initials) मौजूद हैं।
- रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि 01.03.2000 की अस्थायी ओवरड्राफ्ट को मैनेजर ने सीएसई के दबाव में आकर मंज़ूरी दी थी, और 25.03.2000 तथा 31.03.2000 की डेबिट एंट्रीज़ चार्जशीटेड कर्मचारी ने धोखाधड़ी से की थीं; और बचाव पक्ष का यह तर्क कि इन एंट्रीज़ को प्रमाणित किया गया था, सच नहीं है। दूसरी ओर, सभी सबूत यह दिखाते हैं कि दोनों सीएसई ने आपस में मिलीभगत की थी, और सीएसई ने मैनेजर के पद का अनुचित लाभ उठाते हुए, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी वाली एंट्रीज़ की थीं।
- यह बचाव पक्ष का दावा कि 01.03.2000 की अस्थायी ओवरड्राफ्ट और 03.04.2000 को एफजीसी 1/2000 देना, सामान्य कामकाज के तहत किया गया था, सच नहीं है। सबूतों से पता चलता है कि इसमें सीएसई और श्री रॉबर्ट आर. हूवर शामिल थे, जिन्होंने दबाव के कारण आरोपी कर्मचारी की मदद की थी। इसके अलावा, एमएक्स-1, और एमएक्स-13 और 14 के अनुसार, 24.03.2000, 25.03.2000 और 31.03.2000 की एसबी कंट्रोल एंट्री सीएसई की लिखावट में हैं। एमएक्स-8 के अनुसार, सीएसई ने 25.03.2000 को एसबी 1550 में 25,000/- रुपये सिर्फ लेजर खाते में डेबिट किए थे, लेकिन सब्सिडियरी (एमएक्स-14) और एसबी कंट्रोल रजिस्टर (एमएक्स-13) में इसकी एंट्री नहीं की थी। अगर एमएक्स-8 में की गई एंट्री, जैसा कि बचाव पक्ष के प्रतिनिधि ने दावा किया है, सही होती, तो वह एमएक्स-13 और 14 में भी दिखाई देनी चाहिए थी।
- सीएसई द्वारा दिनांक 31.03.2000 को 25,000/- रुपये की डेबिट एंट्री एसबी लेजर 2 सब्सिडियरी (अर्थात् एमएक्स-14) में अपनी स्वयं की लिखावट में की गई थी, और एसबी 1550 लेजर शीट में कोई एंट्री नहीं की गई थी।
- <u>एमडब्लू 2 द्वारा बैलेंसिंग करने के बाद, एसबी कंट्रोल रजिस्टर (एमएक्स 13) में मौजूद बैलेंस को सीएसई की लिखावट में बदल दिया गया था; यह बदलाव नंगी आँखों से और साथ ही बैलेंसिंग एक्सट्रैक्ट में भी साफ़ दिखाई देता है। डीएक्स-1 में भी सीएसई की लिखावट में बदलाव किया गया था, और सीएसई द्वारा ही उस पर अपने शुरुआती हस्ताक्षर (initials) भी किए गए थे।</u>

[विशेष ज़ोर दिया गया]

- एमडब्लू 1 के बयान के अनुसार, एमएक्स -13 और डीएक्स -1 में दो और हस्ताक्षर हैं, और उनमें से एक सुपरवाइज़र का हो सकता है।

- लेकिन यह सच है कि एक हस्ताक्षर सीएसई का है और दूसरा उस मैनेजर का, जिसने सीएसई के साथ मिलीभगत की थी और जाँच के दौरान यह स्वीकार किया था कि ये सभी प्रविष्टियाँ सीएसई के अनुरोध पर, उसे धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थीं।
- एसबी 1550 में बिना अनुमति के डेबिट करने और एसबी कंट्रोल रजिस्टर तथा एसबी बैलेंसिंग बुक में फेरबदल करने के आरोप को बचाव पक्ष द्वारा गलत साबित या खंडित नहीं किया गया है। हालाँकि 31.03.2000 की क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री और 31.03.2000 के बैलेंसिंग की एंट्री सही लगती हैं, लेकिन 24.03.2000, 25.03.2000 और 31.03.2000 की पिछली एंट्री और 03.04.2000 को एसबी 1/2000 की मंजूरी, ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 31.03.2000 को किए गए फेरबदल, सीएसई द्वारा अपने निजी फायदे के लिए की गई सभी बिना अनुमति वाली एंट्री को छिपाने के लिए किए गए थे।
- यह 25.03.2000 को लाया गया था और लेजर शीट 1550 में दर्ज है। 28.03.2000 से 03.04.2000 के दौरान, रिकॉर्ड में यह बात सामने आई कि एसबी 1550 की लेजर शीट में 03.04.2000 को की गई 25,000/- रुपये की डेबिट एंट्री और 25,000/- रुपये की क्रेडिट एंट्री, एसबी की पासबुक में नहीं दिखाई गई हैं। रिकॉर्ड में यह बात भी सामने आई कि एसबी 1550 की लेजर शीट में 25.03.2000 को की गई 25,000/- रुपये की डेबिट एंट्री और 03.04.2000 को की गई 25,000/- रुपये की क्रेडिट एंट्री, एसबी 1550 की पासबुक में नहीं दिखाई गई हैं। जाँच के दौरान, श्री रामकृष्णैया को 28.07.2004 को ब्रांच में बुलाया गया, और उन्होंने बताया कि 25.03.2000 की एंट्रीज़ उनसे संबंधित नहीं हैं। एमडब्लू ने अपनी जाँच रिपोर्ट में कहा है कि सीएसई ने पासबुक अपनी खुद की लिखावट में लिखी थी। सीएसई ने जाँच के दौरान यह स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर ऊपर बताई गई दो एंट्रीज़ को छोड़ते हुए, श्री रामकृष्णैया की एसबी 1550 की पासबुक लिखी थी। श्री रामकृष्णैया ने एमएक्स-9 के माध्यम से कहा है कि उन्होंने न तो 25.03.2000 को और न ही 03.04.2000 को किसी एफजीसी लोन की मांग की थी, और उन्होंने बैंक से कभी कोई लोन नहीं लिया। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

- रिकॉर्ड पर यह बात लाई गई है कि 13.10.99 को 26,000/- रुपये की डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास बुक में, यानी एमएक्स -.15 में नहीं की गई थी। लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है, ब्रांच ने 31.03.2000 को प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 100/- रुपये डेबिट किए थे, जो 13.10.99 को मंज़ूर किए गए जीएल 168/99 के संबंध में थे। हालाँकि, 25.03.2000 की डेबिट एंट्री के मामले

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

- में;— वही एंट्री 25.03.2000 को एसबी सब्सिडियरी में दर्ज नहीं की गई थी, और 03.04.2000 की क्रेडिट एंट्री के मामले में, लोन एफजीसी 1/00 श्री रामकृष्णैया के नाम पर मंज़ूर नहीं किया गया था। चूँकि सीएसई को 24.03.2000 को एसबी अकाउंट 1550 में 298937/- रुपये के बड़े क्रेडिट के बारे में पता था, इसलिए उसने मैनेजर की जानकारी के बिना अकाउंट से 25,000/- रुपये डेबिट कर लिए थे। बचाव पक्ष ने रिकॉर्ड पर यह लाने की कोशिश की है कि 13.10.99 की एंट्री पास बुक में नहीं दिखाई दे रही थी, और इसी के अनुसार, 25.03.2000 और 03.04.2000 की एंट्री भी पास बुक में नहीं दिखाई दे रही थीं, और बचाव पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि सीएसई का यह काम जान-बूझकर नहीं किया गया था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, 25.03.2000 और 03.04.2000 की एंट्री को छोड़ना जान-बूझकर किया गया था, और अकाउंट होल्डर, यानी श्री रामकृष्णैया ने जीएल 168/99 के संबंध में 13.10.99 और 31.03.00 की एंट्री के बारे में कभी कोई आपत्ति/शिकायत नहीं की थी (एमएक्स - 9), और श्री रामकृष्णैया का 25.03.2000 और 03.04.2000 के लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं था।

[विशेष ज़ोर दिया गया]

- सीएसई ने अपने 24.07.04 के बयान में यह स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुवर्णम्मा के नाम पर एसबी खाता 2450 खुलवाया था, जो न तो कहीं नौकरी करती हैं और न ही कोई व्यवसाय करती हैं, बल्कि वे सिलाई प्रशिक्षण कक्षा में जाती थीं। उक्त खाते में उन्होंने "8" बार अस्थायी ओवरड्राफ्ट लिए और उन्हें चुका भी दिया। सीएसई ने अपनी पत्नी के नाम पर 20,000/- रुपये का ऋण डीपीएन(आरटी) 22/98, 25,000/- रुपये का डीपीएन(आरटी) 31/99 और 72,57,000/- रुपये का एएलएस 15/2003 लेने की बात भी स्वीकार की थी। उन पर यह आरोप है कि उपरोक्त अस्थायी ओवरड्राफ्ट /ऋणों के लिए नियंत्रण कार्यालय की सहमति नहीं ली गई थी।

[विशेष ज़ोर दिया गया]

- बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया है कि सीएसई, सर्कल ऑफिस से सहमति न मिलने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को दिए जाने वाले लोन/एडवांस के लिए कंट्रोलिंग ऑफिस से सहमति लेने के संबंध में बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। हालाँकि, कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को लोन देने से पहले, कंट्रोलिंग

ऑफिस से सहमति लेना ब्रांच मैनेजर की ज़िम्मेदारी है, फिर भी संबंधित कर्मचारी को भी इस संबंध में दिलचस्पी/पहल करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि मैनेजर ने सहमति ली है या नहीं, ताकि उसका अपना हित सुरक्षित रहे।

- इस मामले में, बचाव पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने गलत कर्मचारी पर सही आरोप लगाया है। बचाव पक्ष ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि सीएसई ने बैंक के एक ज़िम्मेदार कर्मचारी के तौर पर, मैनेजर को सहमति लेने की याद दिलाने की पहल भी की थी। जब सीएसई ने अपनी पत्नी के नाम पर विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने में पहल की थी, तो उसे कंट्रोलिंग ऑफिस से सहमति लेने में भी उतनी ही दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी।
- रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि सीएसई ने अपने निजी फ़ायदे के लिए पैसे जुटाने के मकसद से, एसबी खाता 1550 में बिना इजाज़त के डेबिट किए हैं। उसने अपने परिवार के सदस्यों को निजी फ़ायदे के लिए लोन मंज़ूर करवाने के लिए मैनेजर पर दबाव डाला था। उसने बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है; उसने एसबी कंट्रोल रजिस्टर, एसबी सब्सिडियरी शीट्स और एसबी बैलेंसिंग बुक में बदलाव करके, बिना इजाज़त के किए गए डेबिट्स की वजह से खातों को धोखाधड़ी के तरीकों से मिलाया है।
- सीएसई ने अपनी पत्नी के नाम पर ऋण/अस्थायी ओवरड्राफ्ट लिए थे, जिसके लिए उन्होंने नियंत्रक कार्यालय से सहमति प्राप्त करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है।
- मैंने पाया है कि सीएसई के सभी तर्कों को जांच अधिकारी ने अपनी 09.01.2006 की रिपोर्ट में शामिल किया है, और सीएसई ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए कोई भी ऐसा वैध आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो विचारणीय हो। अतः, जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, मैं सीएसई को इस आदेश में सूचीबद्ध आरोपों का दोषी ठहराता हूँ और तदनुसार आदेश देता हूँ।

- इस आदेश की एक प्रति श्री गंगरासिम्हैया को भेजी जाएगी।

स्थान: सीओ, बेंगलुरु

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

दिनांक: 15.03.2006

हस्ताक्षार/-
उप महाप्रबंधक
अनुशासनात्मक प्राधिकारी

केनरा बैंक
संदर्भ: बीएलसी:डीएसी:4421:E-37:2006

अनुशासनात्मक प्राधिकारी
सर्कल कार्यालय, बेंगलुरु

उप महाप्रबंधक की कार्यवाहियाँ

विषय: श्री गंगरासिम्हैया (61633), सब-स्टाफ़ (U/s), केनरा बैंक, शाखा - बोमनासंद्रा द्वारा कथित कदाचार के मामले में।

संदर्भ: 1. आरोप-पत्र सं० बीएलसी:डीएसी:3038:E-37:सीएच-25/2005, दिनांक 28.04.2005.

2. निलंबन कार्यवाही सं. बीएलसी:एसएसडब्लू:10813:EP:E.37:2004 दिनांक 18.08.2004.

चूँकि, संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध, उसे उपर्युक्त आरोप-पत्र तामील कराकर, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी;

चूँकि, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त आरोप-पत्र की जाँच करने हेतु एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था;

चूँकि, जाँच अधिकारी ने जाँच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कर्मचारी को, उनके निष्कर्षों में सूचीबद्ध आरोपों का "दोषी" पाया;

चूंकि, जांच निष्कर्षों की एक प्रति पत्र संख्या BLCs -DACs 31:2006 दिनांक 09.01.2006 के माध्यम से आरोप-पत्रित कर्मचारी को भेजी गई थी, और आरोप-पत्रित कर्मचारी ने अपने पत्र दिनांक 28.01.2006 के माध्यम से उन निष्कर्षों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं;

जबकि, जांच अधिकारी के निष्कर्षों, आरोप पत्र में उल्लिखित कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर दिए गए बयानों और अन्य संबंधित अभिलेखों

का विश्लेषण करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की;

चूंकि, कदाचार की गंभीरता और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, आरोप-पत्रित कर्मचारी पर "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" का दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया गया था, और इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.2006 को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी;

संदर्भ: सं. बीएलसी:डीएसी:4421:ई-37:2005 दिनांक 15.05.2006

अब इसलिए, पर्सनल हियरिंग के दौरान चार्जशीटेड एम्प्लॉई द्वारा दिए गए सबमिशन, मिसकंडक्ट की गंभीरता, संबंधित रिकॉर्ड, केस के हालात को ध्यान में रखते हुए, इन्क्वायरिंग ऑफिसर के फाइंडिंग्स से सहमत होते हुए और चार्जशीटेड एम्प्लॉई को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऑर्डर में बताए गए चार्जेस के लिए "दोषी" मानते हुए, सज़ा दी जाती है।

"अनिवार्य सेवानिवृत्ति"

केनरा बैंक सेवा संहिता के अध्याय XI, विनियम 4, खंड (बी) के अंतर्गत परिकल्पित दंड, एतद्द्वारा संबंधित कर्मचारी पर अधिरोपित किया जाता है।

निलंबन की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा, और साथ ही निलंबन की अवधि के लिए वेतन वृद्धि भी जारी नहीं की जाएगी।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति संलग्न है।
सर्कल कार्यालय, बैंगलोर
दिनांक: 15.03.2006

26. इसके बाद, उत्तरदाता ने अपीलीय प्राधिकारी, यानी केनरा बैंक के महाप्रबंधक के समक्ष एक अपील दायर की; और अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त अपील में उठाए गए आधारों पर विचार करने के बाद, दिनांक 22.11.2006 के आदेश द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निम्नानुसार है:-

- अपील ज्ञापन, जाँच की कार्यवाही, जाँच अधिकारी के निष्कर्षों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया।

- श्री गंगानरसिम्हाइया को 02/11/2006 को बैंगलोर स्थित प्रधान कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, और उनकी दलीलों को सुना तथा दर्ज किया गया।

- श्री गंगानरसिम्हाइया 11.11.1997 से 01.08.2004 तक हमारी वी.जी.डोड्डी शाखा में कार्यरत थे; इसके बाद 02.08.2004 को उन्होंने बोम्मासंद्रा शाखा में कार्यभार ग्रहण किया, और 19.08.2004 को उन्हें निलंबित कर दिया गया।

- हमारी वी.जी.डोड्डी ब्रांच के एडवांसेज़ पोर्टफोलियो में गंभीर विसंगतियां देखी गईं। इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि श्री गंगनारसिम्हाइया ने अपने निजी फायदे के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से, एसबी खाता 1550 में बिना किसी अधिकार के डेबिट किए हैं। उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को लोन मंज़ूर करवाने हेतु मैनेजर पर दबाव डाला है। उन्होंने बिना अधिकार किए गए डेबिट के कारण खातों को धोखाधड़ी से मिलाने के लिए, बैलेंसिंग बुक, की रजिस्टर और एसबी सुब्सीडियरी शीट्स में बदलाव करके बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है।

- अपने उपरोक्त कार्यों के द्वारा, वह अत्यंत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है। ये आरोप ऊपर उल्लिखित आरोप-पत्र में पूर्ण रूप से सूचीबद्ध हैं।

- जांच किए जाने पर, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता को आरोपों का दोषी पाया। जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने संबंधित दंड अधिरोपित किया है।

- उपर्युक्त दंड अधिरोपित किए जाने से व्यथित होकर, श्री गंगनारसिम्हाइया ने यह अपील प्रस्तुत की है, जिस पर विधिवत विचार किया गया है।

- अभिलेखों का अवलोकन करने पर, मैं निम्नलिखित बातें पाता हूँ:

- 3/4/2000 को, श्री कंबैया को 25,000 रुपये का एफजीसी लोन दिया गया था, जिनके बारे में बताया गया है कि वे अपीलकर्ता के पिता हैं। एफजीसी 1/2000 के लिए एक डेबिट स्लिप तैयार की गई थी और श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 के लिए एक संबंधित क्रेडिट स्लिप तैयार की गई थी। यह पता चला है कि एसबी 1550 की लेजर शीट में, 25/3/2000 को "To एफजीसी 172000" के रूप में 25,000 रुपये का डेबिट था, और 3/4/2000 को "By एफजीसी" के रूप में 25,000 रुपये का क्रेडिट किया गया था। सभी लेजर प्रविष्टियाँ अपीलकर्ता

की लिखावट में की गई हैं। 25/3/2000 के स्लिप बंडल में कोई संबंधित डेबिट या क्रेडिट स्लिप नहीं थी। 31/3/2000 के स्लिप बंडल में, श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 को डेबिट करने वाली 25,000 रुपये की एक डेबिट स्लिप थी, जिस पर एफजीसी 1/2000" लिखा था, और एफजीसी 1/2000 को क्रेडिट करने के लिए उतनी ही राशि की एक क्रेडिट स्लिप थी। डेबिट स्लिप पर लेजर फोलियो नंबर 7812 अंकित है, जिस पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर हैं, और यह स्लिप श्री आर. आर. हूवर द्वारा जारी की गई थी। एसबी लेजर का बैलेंस श्री चन्नवेंकटैया, जो शाखा के PTE थे, द्वारा निकाला गया था। कुल बैलेंस को बदलकर 2,75,196 रुपये कर दिया गया था और बैलेंस का मिलान हो गया था। एसबी बैलेंसिंग बुक में किए गए संबंधित बदलावों को स्वीकार किया गया है कि वे अपीलकर्ता की लिखावट में हैं; एसबी की रजिस्टर भी अपीलकर्ता की लिखावट में लिखा गया था और अंतिम कुल योग को व्हाइट फ्लूइड लगाकर बदला गया था और उस पर अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने मैनेजर की जानकारी के बिना श्री रामकृष्णैया के खाते को गलत तरीके से डेबिट किया था। एसबी खाता 1550 से 25/3/2000 को 25,000/- रुपये की निकासी और उसमें किए गए बदलावों (यानी एसबी की रजिस्टर और एसबी बैलेंसिंग बुक में) के बारे में श्री रॉबर्ट आर हूवर को 31/3/2000 को पता चला। श्री रॉबर्ट आर हूवर ने बताया है कि इस मामले की सूचना सर्कल ऑफिस को नहीं दी गई थी, क्योंकि अपीलकर्ता ने दया की गुहार लगाई थी... उपरोक्त लेन-देनों को ठीक करने के लिए, श्री रॉबर्ट आर हूवर ने 31/3/2000 को ट्रांसफर स्लिप बनाईं, जिसमें उन्होंने एसबी 1550 से राशि निकालकर (डेबिट करके) उसे एफजीसी मद में जमा (क्रेडिट) कर दिया। अपीलकर्ता ने एसबी 1550 की पास-बुक में जान-बूझकर उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों को छोड़ दिया था, जिसे उसने लिखित रूप में स्वीकार भी किया है।

- अपीलकर्ता ने अपने 24.07.2004 के बयान में स्वीकार किया कि उसने 19.12.1997 को अपनी पत्नी श्रीमती सुवर्णम्मा के नाम पर एसबी 2450 खाता खुलवाया था। वह कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करती हैं, लेकिन सिलाई प्रशिक्षण कक्षाओं में जाती हैं। उसने इस खाते में अस्थायी ओवरड्राफ्ट लिए थे और उन्हें चुका भी दिया था। अपीलकर्ता ने संबंधित पर्चियों को अपनी ही लिखावट में दर्ज किया था। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर 20,000 रुपये का डीपीएनआरटी 22/98, 25,000 रुपये का

डीपीएनआरटी 31/99 और 25,000 रुपये का एएलएस 15/2003 लिया था। अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने एफजीसी 1/2000 की पर्चियों को एसबी 519 (अपीलकर्ता के पिता श्री कंबैया का खाता) और एसबी 1550 के एसबी लेजर शीट में दर्ज किया था, और यह भी कि श्री रामकृष्णैया के एसबी 1550 और उसके पिता के एफजीसी 1/2000 के बीच कोई संबंध नहीं था; साथ ही, एसबी 1550 से 25,000 रुपये डेबिट किए जाने की जानकारी श्री रामकृष्णैया को नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि श्री रामकृष्णैया 25.03.2000 से 03.04.2000 तक अपनी ही राशि से वंचित रहे। अपीलकर्ता ने अपने 28.07.2004 के बयान में स्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर एफजीसी 1/2000 से संबंधित विवरणों को छोड़ते हुए पासबुक संख्या 1550 में प्रविष्टियाँ की थीं। अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने एसबी 2959 की एसबी लेजर शीट संख्या 549518 में प्रविष्टियाँ की थीं, जो श्री जॉर्ज जोसेफ से संबंधित है।

- एमएक्स-4 के ज़रिए यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि श्री रॉबर्ट आर. हूवर ने, अपीलकर्ता के कहने पर, श्री कंबैया के एसबी 519 खाते में 10,000/- रुपये का अस्थायी ओवरड्राफ़्ट मंज़ूर किया। इस TOD को क्लियर करने के लिए, उन्होंने एफजीसी 1/2000 की एक डेबिट स्लिप तैयार की। हालाँकि, अपीलकर्ता ने एसबी खाता 1550 से राशि डेबिट कर दी। श्री रॉबर्ट आर. हूवर ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता ने एसबी बैलेंसिंग और एसबी कंट्रोल रजिस्टर में लिखे अंकों में फेरबदल किया था।

- अस्थायी ओवरड्राफ्ट 15 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहा, और 24.03.2000 को 25,000/- रुपये की एक एंट्री पोस्ट करके इसे समायोजित किया गया, जिसका विवरण "एफजीसी 1/2000" था। यह एंट्री अपीलकर्ता द्वारा पोस्ट की गई थी, हालाँकि इस पर मैनेजर के हस्ताक्षर थे।

- रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि अपीलकर्ता ने 01.03.2000 को मैनेजर से संपर्क किया और अपने पिता के खाते में 10,000 रुपये के अस्थायी ओवरड्राफ्ट के लिए उन पर दबाव डाला, जिसे उन्होंने 7 दिनों के भीतर चुकाने की अनुमति दी थी। 24.03.2000 को, अपीलकर्ता ने फिर से मैनेजर से संपर्क किया और 25,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी, और उन पर दबाव डालकर एफजीसी और एसबी खाते के लिए 25,000 रुपये की डेबिट और क्रेडिट पर्ची तैयार करवाई; उसने कहा था कि उसके पिता उसी दिन ऋण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए शाखा में आएंगे। श्री कंबैया वहां नहीं आए, लेकिन राशि निकाल ली गई; इसके बाद, 25.03.2000 को, मैनेजर की

जानकारी के बिना ही, श्री रामकृष्णैया के एसबी खाता संख्या 1550 से 25,000 रुपये डेबिट कर दिए गए। पर्चियों के बंडलों में इससे संबंधित कोई डेबिट या क्रेडिट पर्ची मौजूद नहीं है। 31.03.2000 को, श्री रामकृष्णैया के एसबी खाता संख्या 1550 के लिए 25,000 रुपये की एक डेबिट पर्ची मिली, जिस पर लेजर फोलियो संख्या 7812 अंकित है और उस पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

- सभी सबूतों से यह ज़ाहिर होता है कि अपीलकर्ता और उस समय के मैनेजर श्री आर. आर. हूवर, दोनों ने मिलकर साठ-गांठ की और आर्थिक फ़ायदा उठाने के लिए फ़र्ज़ी एंट्रीज़ कीं। उपरोक्त बातों को देखते हुए, अपीलकर्ता के तर्कों में कोई दम नहीं है।
- अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों से साबित होते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि जांच के दौरान श्री रामकृष्णैया और श्री आर.आर. हूवर से पूछताछ नहीं की गई, इससे एमएक्स-4 और एमएक्स-9 (उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान) के ज़रिए रिकॉर्ड पर लाए गए सबूत अमान्य नहीं हो जाएंगे।
- अपीलकर्ता ने स्वयं अपने हाथ से बयान (यानी एमएक्स-2 और एमएक्स-3) दर्ज किए हैं, और उनके सभी बयान श्री H. N. रमेश, मैनेजर (जांच अधिकारी) को संबोधित हैं। बचाव पक्ष भी जांच के दौरान ऐसा कोई भी सबूत–चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी–पेश करने में विफल रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि इस मामले में जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी और यह रिपोर्ट मनगढ़ंत है।
- बैंक द्वारा कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों/अग्रिमों के लिए कंट्रोलिंग ऑफिस से सहमति प्राप्त करने के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यद्यपि कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को ऋण देने से पहले कंट्रोलिंग ऑफिस से सहमति प्राप्त करना ब्रांच मैनेजर की ज़िम्मेदारी है, फिर भी संबंधित कर्मचारी को भी इस संबंध में रुचि/पहल करनी चाहिए और अपने सर्वोत्तम हित के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैनेजर ने सहमति प्राप्त की है या नहीं।
- अपीलकर्ता पर लगाया गया दंड उसके कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में ऐसे कोई वैध आधार या तर्क प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सके। इस अपील में कोई सार नहीं है। अतः, इस अपील को अस्वीकृत किया जा सकता है।

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

- उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मुझे जाँच अधिकारी के निष्कर्षों अथवा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। अतः, मैं दंड की पुष्टि करता हूँ और तदनुसार अपील अस्वीकृत मानी जाएगी।

  इस आदेश की एक प्रति श्री गंगरासिम्हैया को भेजी जाएगी।

  हस्ताक्षर/-
  महाप्रबंधक
  अपीलीय प्राधिकारी
  22.11.2006

27. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ट्रिब्यूनल ने दिनांक 17.05.2013 के आदेश के माध्यम से, प्रारंभिक जांच पर निर्णय लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि उत्तरदाता के विरुद्ध की गई जांच निष्पक्ष थी और उक्त आदेश को अंतिम रूप प्राप्त हो चुका था। तथापि, दिनांक 25.09.2019 का अंतिम अधिनिर्णय पारित करते समय, ट्रिब्यूनल ने उत्तरदाता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। अंतिम अधिनिर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है।

- "...जांच अधिकारी के सामने रखे गए सबूतों की जांच करने पर, यह साफ़ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह दिखाता हो कि CSE ने मैनेजमेंट के किसी भी दिखाए गए दस्तावेज़ में कोई एंट्री की थी। उसके किसी भी सहकर्मी को जांच अधिकारी के सामने यह गवाही देने के लिए नहीं लाया गया कि मैनेजमेंट के दस्तावेज़ों में की गई एंट्रीज़ उसी ने लिखी थीं। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान अपने आप में सबूत के तौर पर काम नहीं करते। चूंकि इन बयानों पर जिरह (क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन) नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें सबूत के तौर पर मानने लायक नहीं माना जा सकता। एमडब्लू-2 के सबूतों से यह साबित होता है कि, एक पार्ट-टाइम कर्मचारी ने भी रिकॉर्ड में एंट्रीज़ की थीं और एसबी A/c 1550 से जुड़ा कुल हिसाब 31.03.2000 को मेल नहीं खा रहा था, और बाद में किसी ने उस एंट्री को ठीक कर दिया। उसने कभी यह नहीं कहा कि उसने पहले पक्ष को बैंक के रिकॉर्ड संभालते हुए देखा था। पहला पक्ष, जो कर्मचारी है, वह 'सब-स्टाफ़' है और उसकी शैक्षिक योग्यता 7वीं कक्षा तक है। इस बात पर किसी विशेषज्ञ की राय लेने की कोई कोशिश

नहीं की गई कि विवादित एंट्रीज़ पहले पक्ष के कर्मचारी ने ही लिखी थीं। उसने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथाकथित बयान पर आपत्ति जताई है। 'सब-स्टाफ़' होने के नाते, यह सोचना कोरी कल्पना है कि वह इतनी मज़बूत स्थिति में था कि वह अपने सीनियर अधिकारी / बैंक मैनेजर पर दबाव डालकर, नियमों का उल्लंघन करते हुए लोन मंज़ूर करवा सके। अब उसकी ओर से यह दलील दी गई है कि, उसके पिता और पत्नी के पक्ष में मंज़ूर किए गए सभी लोन चुका दिए गए हैं। उसके पिता उससे अलग रहते हैं और उसकी पत्नी अपनी खुद की कमाई करती है। मैं इस दलील से सहमत नहीं हो सकता; अगर सच में यही हकीकत होती, तो उसे जांच के दौरान अपने पिता और पत्नी को गवाह के तौर पर पेश करना चाहिए था। शुरुआती मुद्दे पर फ़ैसला आने के बाद, उसने यह दावा करते हुए सबूत पेश किए कि उसके माता-पिता और पत्नी उस पर निर्भर हैं। उसके अपने सबूतों और उसकी दलीलों के बीच विरोधाभास है।

9. आइए, हम आरोपों की जाँच अलग-अलग हिस्सों में करें। हालाँकि, उनके पिता श्री कंबैया को 03.04.2000 को 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हज़ार रुपये) का लोन मंज़ूर किया गया था, फिर भी पहले पक्ष ने 25,000/- रुपये (पच्चीस हज़ार रुपये) के अतिरिक्त लोन का अनुरोध किया। लोन के कागज़ात पूरे किए बिना ही, पहले पक्ष ने श्री कंबैया के एसबी खाता 519 में क्रेडिट स्लिप जमा कर दीं और 24.03.2000 को उक्त खाते से 15,000/- रुपये (केवल पंद्रह हज़ार रुपये) निकाल लिए; यह साबित नहीं हुआ है कि एसबी खाता में यह एंट्री पहले पक्ष ने ही की थी। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, एसबी खाता में एंट्री संबंधित क्लर्क द्वारा की जानी चाहिए थी। यदि पहले पक्ष ने ऐसी कोई एंट्री की भी थी, तो रिकॉर्ड के अनुसार इस बात की गवाही देने के लिए या तो मैनेजर होना चाहिए था या फिर संबंधित क्लर्क। 15,000/- रुपये से संबंधित चेक या विड्रॉल स्लिप पेश नहीं की गई है।

- दिनांक 25.03.2000 को उन्होंने श्री रामा कृष्णायाह के एसबी खाता सं० 1550 से अनधिकृत रूप से राशि डेबिट की; दिनांक 25.03.2000 की क्रेडिट स्लिप और डेबिट स्लिप तथा दैनिक नियंत्रण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- एक बार फिर, यह साबित नहीं हुआ है कि एसबी खाता स्टेटमेंट/एमएक्स-8 में संबंधित एंट्री प्रथम पक्ष के कामगार की है।
- उसने सहायक शीट में संबंधित प्रविष्टि नहीं की है–लेकिन यह एक सब-स्टाफ़ का कर्तव्य नहीं है।
- उपर्युक्त लेन-देन की जानकारी प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 31.03.2000 को प्रबंधक के संज्ञान में लाई गई, जिस पर प्रबंधक ने दिनांक 31.03.2000 को

श्री राम कृष्ण के एसबी खाते को डेबिट करके तथा एफजीसी सब्सिडियरी को डेबिट करके पर्चियों को पारित कर दिया–किंतु साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होती है।

- यह कि डेबिट स्लिप उन्होंने श्री कंबैया के लोन अकाउंट एमएक्स-12 में अपने निजी फ़ायदे के लिए पोस्ट की थी। यह साबित नहीं हुआ है कि एक्स एमएक्स-12 में की गई एंट्रीज़ के लेखक (Author) पहली पार्टी ही हैं, हालाँकि शायद उन्होंने मंज़ूर की गई लोन की रकम का फ़ायदा उठाया हो। उन्होंने बैलेंसिंग बुक में बदलाव किए और जान-बूझकर 2,75,196/- रुपये (सिर्फ़ दो लाख पचहत्तर हज़ार एक सौ छियानवे रुपये) का बदलाव किया ताकि बैलेंस मिल जाए। उन्होंने एसबी कंट्रोल रजिस्टर और सब्सिडियरी लेजर में क्लोजिंग बैलेंस में बदलाव किए ताकि बुक का मिलान हो सके - लेकिन जाँच के दौरान एसबी कंट्रोल रजिस्टर, बैलेंसिंग बुक और सब्सिडियरी लेजर पेश नहीं किए गए।
- श्री रामा कृष्णायाह के एसबी खाते में हुई अनाधिकृत डेबिट प्रविष्टि को छिपाने के उद्देश्य से, प्रथम पक्ष ने पासबुक अपडेट करते समय डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को छोड़ दिया। न केवल प्रथम पक्ष के पास पासबुक में प्रविष्टि करने का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि रामा कृष्णा की पासबुक में की गई प्रविष्टियों का कर्ता वही था।
- श्रीमती सुवर्णम्मा के एसबी खाते में TOD की अनुमति दी गई और श्री कंबैया को ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि इसके लिए नियंत्रक कार्यालय की सहमति नहीं ली गई थी; इस चूक की सीधी ज़िम्मेदारी प्रबंधक की है।
- पूरे सबूतों का नतीजा यह था कि प्रथम पक्ष के कामगार के पिता और पत्नी को गलत तरीके से लोन दिया गया था। दोनों 1st पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए यह बहुत मुमकिन है कि 1st पार्टी के कहने पर मैनेजर ने चार्जशीट में बताई गई गड़बड़ियां की हों। हालांकि, 1st पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और न ही बैंक को इस कथित घटना से कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ। सिर्फ सबूत के साथ या बिना सबूत के सस्पेंशन कानूनी सबूत का काम नहीं कर सकता। बैंक के रिकॉर्ड में हेराफेरी में 1 पार्टी के कामगार की मिलीभगत साबित करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में, जांच अधिकारी का यह नतीजा कि-

I. उसने एसबी खाता 1550 में अनधिकृत रूप से डेबिट किया।

II. उन्होंने मैनेजर पर लोन मंज़ूर करने के लिए दबाव डाला,

III. उसने बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की।

- साक्ष्य सामग्री की नींव के बिना, यह निर्णय विकृत है। अतः, ऐसी अपूर्ण और कमज़ोर निष्कर्षों के आधार पर पारित दंडादेश अवैध है।

10. यह सब कहने के बाद, अब ध्यान इस बात पर है कि किस तरह की राहत दी जाए। हालाँकि पहला पक्ष कथित दुराचार में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन यह साफ़ है कि वह इस दुराचार / अनियमित लोन मंज़ूरी का लाभार्थी था। पहले पक्ष के कर्मचारी को, जो अपने करियर के बीच में था और जिस पर परिवार पालने की ज़िम्मेदारी थी, इतने छोटे से कारण पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा देना बहुत ज़्यादा सख़्त और असंगत है। अगर कर्मचारी को नौकरी पर वापस रखा जाता है, तो शायद उसके पास सेवा के कुछ और साल बाकी हैं; वह अभी सेवानिवृत्ति लाभों का आनंद ले रहा है। यह देखते हुए कि वह कथित दुराचार में एक हितधारक पक्ष था, मेरी सुविचारित राय में, बिना पिछले वेतन के, सेवा की निरंतरता के साथ उसे नौकरी पर वापस रखना ही उचित फ़ैसला होगा, जो इस स्थिति के लिए सही रहेगा।

अवार्ड

- संदर्भ स्वीकार किया जाता है। प्रथम पक्ष के कामगार श्री गनगनारसिमैया के विरुद्ध, द्वितीय पक्ष केनरा बैंक द्वारा दिनांक 15.3.2006 को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करने वाला आदेश रद्द किया जाता है।
- दूसरी पार्टी को निर्देश दिया जाता है कि वह काम करने वाले को उसके असली पद पर वापस रखे
- बिना पिछले वेतन के सेवा की निरंतरता।

28. अंतिम निर्णय की बारीकी से जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित था कि विभाग यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि बैंक/ऋण खातों में की गई प्रविष्टियों का लेखक उत्तरदाता ही था, जिसके लिए उसे आरोप-पत्र जारी किया गया था। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ की राय लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि विवादित प्रविष्टियाँ उत्तरदाता द्वारा ही की गई थीं।

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने यह पाया है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप के अनुसार अनियमितताएँ मैनेजर द्वारा उत्तरदाता के कहने पर की गई थीं। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने यह भी दर्ज किया कि बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर के संबंध में उत्तरदाता की मिलीभगत का कोई भी सबूत न होने के कारण, विवादित एसबी खाते में अनाधिकृत डेबिट की एंट्री करने, लोन मंज़ूर करने के लिए मैनेजर पर उत्तरदाता द्वारा दबाव डालने और रिकॉर्ड की किताबों से छेड़छाड़ करने के संबंध में जाँच अधिकारी के निष्कर्षों को सही नहीं माना जा सकता। ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि यद्यपि उत्तरदाता इस कदाचार/अनियमित लोन मंज़ूरी का लाभार्थी था, लेकिन चूँकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह कथित कदाचार में सीधे तौर पर शामिल था, इसलिए उत्तरदाता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देना बहुत कठोर और असंगत था।

29. हैरानी की बात है कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को इस आधार पर सही ठहराया कि उत्तरदाता पर लगाए गए आरोप बेतुके हैं; और चूंकि उत्तरदाता के पिता लोन लेने के हकदार थे और सक्षम अधिकारी ने उन्हें लोन मंज़ूर भी कर दिया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाता के पिता को लोन देने में कोई गैर-कानूनी काम हुआ है। अजीब बात यह है कि हाई कोर्ट ने उत्तरदाता की पत्नी को दिए गए लोन के गैर-कानूनी वितरण से जुड़े आरोप पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट इस बात से भी प्रभावित था कि चूंकि बैंक को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।

30. हमें यह कहते हुए खेद है कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, दोनों ही अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहे। यह भली-भांति स्थापित है कि जब किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कथित कदाचार के लिए कोई अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाती है, और उस जांच में वह दोषी पाया जाता है तथा बाद में उसे दंडित किया जाता है, तो जिस अदालत के समक्ष उस दोषी व्यक्ति द्वारा इस निर्णय को चुनौती दी जाती है, उस अदालत के लिए निम्नलिखित पहलुओं की जांच करना और उनका निर्धारण करना आवश्यक होता है:

I. क्या जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी?

II. प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन किया गया है अथवा नहीं;

III. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, अथवा वे निष्कर्ष विकृत हैं।

यह भी समान रूप से स्थापित है कि विभागीय कार्यवाहियों में साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, और दोषी के विरुद्ध आरोप को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है।

31. इस न्यायालय ने **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारतीय संघ एवं अन्य** के मामले में, जो **(1995) 6 एससीसी 749** में रिपोर्ट किया गया है, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

> **12.** न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, बल्कि यह उस तरीके की समीक्षा है जिस तरह से वह निर्णय लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है, वह न्यायालय की दृष्टि में अनिवार्य रूप से सही हो। जब किसी लोक सेवक पर कदाचार के आरोपों की जाँच की जाती है, तो न्यायालय/अधिकरण का सरोकार यह निर्धारित करने से होता है कि क्या जाँच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी, या क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया गया था। चाहे निष्कर्ष या परिणाम किसी साक्ष्य पर आधारित हों, जाँच करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी के पास तथ्यों का निष्कर्ष या परिणाम निकालने का क्षेत्राधिकार, शक्ति और अधिकार होता है। लेकिन वह निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम, और न ही उसमें परिभाषित तथ्यों या साक्ष्य को साबित करने के नियम, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू होते हैं। जब प्राधिकारी उस साक्ष्य को स्वीकार कर लेता है और निष्कर्ष को उससे समर्थन मिलता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह मानने का हकदार होता है कि दोषी अधिकारी आरोप का दोषी है। न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय/अधिकरण एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है, ताकि वह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सके और साक्ष्य के आधार पर अपने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँच सके। न्यायालय/अधिकरण केवल वहीं हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ प्राधिकारी ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही ऐसे तरीके से की हो जो नैसर्गिक न्याय के नियमों के असंगत हो, या जो जाँच की विधि निर्धारित करने वाले सांविधिक नियमों का उल्लंघन करती हो, अथवा जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष या परिणाम किसी भी साक्ष्य पर आधारित न हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा हो कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस पर कभी न पहुँचा होता, तो न्यायालय/अधिकरण उस निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और राहत को इस प्रकार संशोधित कर सकता है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुरूप हो।
>
> **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

13. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही तथ्यों का एकमात्र निर्णायक होता है। जहाँ अपील प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य या दंड की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की समान शक्ति होती है। किसी अनुशासनात्मक जाँच में, कानूनी साक्ष्य के कठोर प्रमाण और उस साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं होते हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में न्यायालय/अधिकरण के समक्ष बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम एच.सी. गोयल मामले में, इस न्यायालय ने पृष्ठ 728 पर यह अभिनिर्धारित किया कि यदि साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विकृत है, अथवा अभिलेख के अवलोकन से ही उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है, अथवा वह निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 'सर्टिओरारी' (Certiorari) रिट जारी की जा सकती है।

14. यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम एस.एल. अब्बास मामले में, जब ट्रिब्यूनल ने तबादले के आदेश में दखल दिया, तो इस न्यायालय ने यह माना कि ट्रिब्यूनल कोई अपीलीय प्राधिकारी नहीं है जो तबादले के उस सद्भावपूर्ण आदेश की जगह अपना खुद का निर्णय दे सके। ऐसी परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल किसी सरकारी कर्मचारी के तबादले के आदेशों में दखल नहीं दे सकता था। दादरा और नगर हवेली के प्रशासक बनाम एच.पी. वोरा मामले में यह माना गया कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोई अपीलीय प्राधिकारी नहीं है और वह किसी लोक सेवक की कार्यकुशलता की बाधा को हटाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों की भूमिका नहीं निभा सकता। हाल ही में, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम समरेंद्र किशोर एंडो मामले में, इस न्यायालय की एक पीठ–जिसमें हममें से दो (न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति बी.एल. हंसारिया) सदस्य थे ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर विचार किया, जिसने आरोपों को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था; पीठ ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया कि क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय ट्रिब्यूनल के पास साक्ष्य का मूल्यांकन करने की शक्ति है, और यह माना कि कोई भी ट्रिब्यूनल साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता और न ही वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों की जगह अपने खुद के निष्कर्ष दे सकता है। अतः, यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल, अनुशासनात्मक या अपीलीय प्राधिकारी के तथ्यों संबंधी निष्कर्षों की जगह अपने खुद के निष्कर्ष देने के उद्देश्य से, साक्ष्य के मूल्यांकन का कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता।

इस निर्णय का विभिन्न मामलों में लगातार पालन किया गया है।

32. इस न्यायालय ने **स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम आर.सी. श्रीवास्तव** के मामले में, जो **(2021)**

19 एससीसी 281 में रिपोर्ट किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में, अधिकरण स्वयं को अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता है और न ही साक्ष्य की पुनः जांच कर सकता है, और ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-ए द्वारा प्रदत्त अपनी अधिकारिता से बाहर होगा। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> **9.** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि, जब घरेलू जाँच को निष्पक्ष और उचित माना जा चुका है, तो घरेलू जाँच में दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का ट्रिब्यूनल का दायरा सीमित हो जाता है; और जब तक कि कोई निष्कर्ष विकृत न हो और किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो, तब तक ट्रिब्यूनल के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद "1947 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 11-ए के दायरे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।
>
> **10.** हालाँकि, इस मामले में, ट्रिब्यूनल ने खुद को एक अपील अदालत में बदल लिया और न केवल सबूतों की पूरी तरह से फिर से जाँच की, बल्कि इस धारणा पर आगे बढ़ा कि मैनेजमेंट को आरोपों को 'उचित संदेह से परे' साबित करना होगा। इसके अलावा, तीन अधिकारियों के ठोस सबूतों के बावजूद–जिन्हें जवाब देने वाले कर्मचारी ने नशे की हालत में गाली दी थी–ट्रिब्यूनल ने उन सबूतों को पूरी तरह से यह कहकर खारिज कर दिया कि एक चौकीदार (डीडब्लू 1) और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी (डीडब्लू 2) ने अपनी गवाही में कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसे सही ठहराने के लिए, रिकॉर्ड पर एक दस्तावेज़ रखा गया, यानी उस समय का हाज़िरी रजिस्टर। और इस तथ्य के बावजूद कि दोषी कर्मचारी घरेलू जाँच में पेश नहीं हुआ था, फिर भी ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी; यह बात बिल्कुल अप्रत्याशित और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के सामने आई है। इसलिए, जाँच के दौरान दर्ज किए गए दोष-निष्कर्ष में ट्रिब्यूनल का यह हस्तक्षेप न केवल मनमाना है, बल्कि कानून की नज़र में भी मान्य नहीं है।
>
> **11.** घरेलू जाँच के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा यह जाँच करना है कि क्या घरेलू जाँच आयोजित करने की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है, अथवा घरेलू जाँच के दौरान दर्ज किए गए दोष-निर्णय में कोई विकृति (perversity) हुई है। ट्रिब्यूनल

डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

द्वारा अपने विवादित निर्णय में की गई मूल त्रुटि को उच्च न्यायालय ने भी नहीं समझा, और उसने घरेलू जाँच में दर्ज निष्कर्षों पर विचार किए बिना रिट याचिका को खारिज कर दिया; ऐसा करते समय उसने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 'संभावनाओं की प्रबलता' के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा, जिनका पालन घरेलू जाँच में दोष सिद्ध करते समय किया जाना चाहिए था, और इस प्रकार उसने 1947 के अधिनियम की धारा 11-ए के तहत परिभाषित अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। इसके विपरीत, जिन अधिकारियों के साथ कथित तौर पर घोर कदाचार की घटना हुई थी, उन्हें यह नोटिस दिया गया कि उनका आरोप प्रथम दृष्टया ही निराधार और बेबुनियाद है, और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है–जो कि कल्पना से भी परे की बात है। इसके अलावा, जब जाँच के दौरान दोषी उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर देने के बाद यह सिद्ध हो गया था कि आरोप सही हैं, तो जाँच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध माना और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए उत्तरदाता पर सेवा-मुक्ति (dismissal) का दंड अधिरोपित किया।

33. इस न्यायालय ने, **'स्टेट ऑफ़ राजस्थान एवं अन्य बनाम हीम सिंह'** के मामले में, जो **(2021) 12 एससीसी 569** में रिपोर्ट किया गया है–न्यायिक समीक्षा अथवा अनुशासनात्मक मामलों के मुद्दे पर, निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

> **37.** अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा करते समय, दो बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति संयम के नियम को दर्शाती है। दूसरी स्थिति यह तय करती है कि हस्तक्षेप कब किया जा सकता है। संयम का नियम न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करता है। इसका एक वैध कारण है। यह तय करना कि कोई कदाचार हुआ है या नहीं, मुख्य रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका नहीं अपनाते हैं। न ही न्यायाधीश नियोक्ता की भूमिका निभाते हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों का सम्मान करना इस विचार की स्वीकृति है कि अपनी सेवा के कुशल संचालन के लिए नियोक्ता ही जिम्मेदार होता है। अनुशासनात्मक जाँचों को 'प्राकृतिक न्याय' के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन वे साक्ष्य के उन कड़े नियमों से नियंत्रित नहीं होतीं जो न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। इसलिए, सबूत का मानक वह कड़ा मानक नहीं होता जो किसी आपराधिक मुकदमे में लागू होता है (यानी 'उचित संदेह से परे' सबूत), बल्कि यह एक दीवानी मानक होता है जो 'संभावनाओं की प्रबलता' पर

आधारित होता है। 'संभावनाओं की प्रबलता' के नियम के अंतर्गत, संदर्भ और विषय के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इस स्पेक्ट्रम का पहला सिरा सम्मान और स्वायत्तता पर आधारित है – अनुशासनात्मक प्राधिकारी की 'तथ्य-खोजने वाले प्राधिकारी' के रूप में स्थिति का सम्मान करना, और सेवा में अनुशासन व दक्षता बनाए रखने में नियोक्ता की स्वायत्तता को बनाए रखना। इस स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर यह सिद्धांत है कि न्यायालय के पास तब हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र होता है, जब जाँच के निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित न हों, या जब वे 'विकृत' हों। किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न करना, कानून की नज़र में 'तथ्य का विकृत निर्धारण' माना जाता है। 'आनुपातिकता' हमारी न्याय-प्रणाली की एक सुस्थापित विशेषता है। सेवा-संबंधी न्याय-शास्त्र ने लंबे समय से इस बात को मान्यता दी है कि न्यायालय के पास तब हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जब कोई निष्कर्ष या दंड, उपलब्ध साक्ष्य या किए गए कदाचार के अनुपात में न हो (यानी बहुत अधिक या बहुत कम हो)। न्यायिक कौशल इसी बात में निहित है कि इन दो विपरीत स्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए सही मार्ग पर चला जाए। न्यायिक समीक्षा करते समय न्यायाधीश केवल 'हस्तक्षेप न करने' के मंत्र का जाप करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते। यह तय करने के लिए कि किसी अनुशासनात्मक जाँच का निष्कर्ष 'किसी साक्ष्य' पर आधारित है या नहीं, एक प्रारंभिक या न्यूनतम स्तर की जाँच-पड़ताल की जाती है। ऐसा न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कदाचार के आरोप के समर्थन में 'कुछ साक्ष्य' मौजूद हैं, और ताकि किसी भी प्रकार के 'विकृत निर्धारण' से बचा जा सके। लेकिन, इससे अदालत को किसी अनुशासनात्मक जाँच में मिले सबूतों के नतीजों को फिर से जाँचने, या अपनी तरफ़ से कोई ऐसा नज़रिया रखने की इजाज़त नहीं मिलती, जो जज को ज़्यादा सही लगे। ऐसा करना उस पहले सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है। सबसे अहम मार्गदर्शक है–मज़बूत सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल; इसके बिना, जज का काम बेमानी है। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

34. ऊपर बताए गए मामलों में तय किए गए कानून की रोशनी में, अगर हम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अंतिम फैसले का विश्लेषण करें, तो यह साफ़ है कि ट्रिब्यूनल ने इस तरह से काम किया, मानो वह अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ कोई अपील सुन रहा हो। ट्रिब्यूनल इस बात को ध्यान में रखने में नाकाम रहा कि यह एक स्थापित कानून है कि विभागीय कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाही में लागू होने वाले सबूतों के कड़े नियम लागू नहीं किए जा सकते, और कदाचार का आरोप केवल संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर ही साबित किया जाना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने, यह निष्कर्ष दर्ज करने के बावजूद कि बैंक/ऋण खातों में अनियमित प्रविष्टियाँ उत्तरदाता के कहने पर की गई थीं और वह उन अनियमितताओं का लाभार्थी था, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिए गए सज़ा के आदेश में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि विभाग यह साबित करने में नाकाम रहा कि विवादित प्रविष्टियों का कर्ता-धर्ता उत्तरदाता ही था। ट्रिब्यूनल तो यहाँ तक कह गया कि उत्तरदाता के हस्ताक्षरों को साबित करने के लिए लिखावट विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई थी। ट्रिब्यूनल ने इस मामले को इस पूर्व-कल्पित धारणा के साथ निपटाया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में, आपराधिक मामलों में लागू होने वाले सबूतों के कड़े नियम लागू होते हैं, जबकि कानून की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।

35. यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, दोनों ने ही यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि नंगी आँखों से देखने पर यह पता लगाया जा सकता है कि बैंक/ऋण खातों में विवादित प्रविष्टियाँ करने वाला व्यक्ति उत्तरदाता ही है, और अन्य दस्तावेज़ों में भी उसी की लिखावट में, उसके शुरुआती अक्षरों (initials) के साथ फेरबदल किया गया था। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि जाँच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, दोनों ही बैंक अधिकारी थे; वे अपनी दिनचर्या के तहत ग्राहकों के हस्ताक्षरों की तुलना नंगी आँखों से करने के अभ्यस्त रहे होंगे, और इसलिए, उन्हें "बैंकर की नज़र" (banker's eye) के दृष्टिकोण से ग्राहकों और अपने सहकर्मियों के हस्ताक्षरों की पहचान करने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया होगा।

36. इस न्यायालय ने, **इंडियन ओवरसीज़ बैंक एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव** के मामले में–जो **(2022) 3 एससीसी 803** में रिपोर्ट किया गया है–और जिसमें इसी तरह की स्थिति पर विचार किया गया था, निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

> **"17.** हम शुरू में ही इस बात पर ज़ोर देना चाहेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, हाई कोर्ट द्वारा किसी ट्रिब्यूनल के फ़ैसले की जाँच करने में कुछ स्वाभाविक कानूनी सीमाएँ होती हैं। हम इस कोर्ट के फ़ैसले, GE Power India Ltd. बनाम A. Aziz का ज़िक्र कर सकते हैं। अगर कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी गलती नहीं है, या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ है, या रिकॉर्ड को देखने पर कोई स्पष्ट कानूनी गलती नज़र नहीं आती है, तो हाई कोर्ट के लिए एक अपीलीय कोर्ट के तौर पर विवाद के गुण-दोष में जाने का कोई अवसर नहीं होता है। वह भी, दो तरह

के हस्ताक्षरों के संबंध में बनाई गई राय के पहलू पर; जहाँ जाँच बैंक के एक अधिकारी द्वारा की गई थी, जिसने हस्ताक्षरों की केवल सीधी तुलना करके यह राय बनाई कि उनमें अंतर है। इसे "बैंकर की नज़र" के दृष्टिकोण से देखा गया है..."

37. इस न्यायालय ने, **'स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेमी चंद नलवाया' (2011) 4 एससीसी 584** के मामले में, ऐसे प्रकरण पर विचार करते हुए, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी ने बैंक के अभिलेखों में अनियमितता करने का दोषी पाए गए एक बैंक कर्मचारी पर 'सेवा-मुक्ति' का दंड अधिरोपित किया था, निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

7. अब यह बात पक्की हो गई है कि कोर्ट अपील कोर्ट की तरह काम नहीं करेंगे और घरेलू जांच में दिए गए सबूतों की दोबारा जांच नहीं करेंगे, और न ही इस आधार पर दखल देंगे कि रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों पर कोई और राय हो सकती है। अगर जांच सही और निष्पक्ष तरीके से हुई है और नतीजे सबूतों पर आधारित हैं, तो सबूत काफ़ी हैं या नहीं या सबूत कितने भरोसेमंद हैं, यह सवाल डिपार्टमेंटल जांच में नतीजों में दखल देने का आधार नहीं होगा। इसलिए, कोर्ट डिपार्टमेंटल जांच में दर्ज तथ्यों के नतीजों में दखल नहीं देंगे, सिवाय तब जब ऐसे नतीजे बिना किसी सबूत के हों या वे साफ तौर पर गलत हों। गलत होने का पता लगाने का टेस्ट यह देखना है कि क्या कोई ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम करते हुए रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों के आधार पर ऐसे नतीजे या नतीजे पर पहुंच सकता था। हालांकि, कोर्ट डिसिप्लिनरी मामलों में नतीजों में दखल देंगे, अगर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों या कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया हो या अगर आदेश मनमाना, मनमानी, गलत इरादे से या बाहरी बातों पर आधारित पाया गया हो। (देखें बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम जी. गणयुथम, बैंक ऑफ इंडिया बनाम डेगाला सूर्यनारायण और बॉम्बे उच्च न्यायालय बनाम शशिकांत एस. पाटिल।

8. जब कोई अदालत इस बात पर विचार कर रही हो कि किसी बैंक कर्मचारी पर "सेवा से बर्खास्तगी" की जो सज़ा दी गई है, वह कहीं बहुत ज़्यादा या साबित हुए दुराचार की गंभीरता के अनुपात में अनुचित तो नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी पर से विश्वास उठ जाना एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारक माना जाएगा। जब कोई अनजान व्यक्ति बैंक में आता है और यह दावा करता है कि वह एक ऐसे खाते का खाताधारक है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है,

और बैंक का कोई कर्मचारी, जो उस व्यक्ति को नहीं जानता, अपने सहकर्मी को निर्देश देता है कि उस खाते को "निष्क्रिय" श्रेणी से "सक्रिय" श्रेणी में बदल दिया जाए (जो कि निष्क्रिय खातों को नियंत्रित करने वाले निर्देशों के विपरीत है) और वह भी बिना किसी तरह के सत्यापन के; और जब वह ऐसे व्यक्ति से पैसे निकालने का फॉर्म स्वीकार कर लेता है, टोकन लेता है, और उस व्यक्ति की ओर से पैसे निकाल लेता है ताकि वह पैसे उस व्यक्ति को सौंप सके–तो असल में वह उस अनजान व्यक्ति को बैंकिंग प्रक्रियाओं के विपरीत जाकर पैसे निकालने में मदद करता है। और अंततः, यदि यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने खुद को खाताधारक बताया था, वह असल में कोई धोखेबाज़ था, तो बैंक को गलत नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह यह कहता है कि संबंधित कर्मचारी पर से उसका विश्वास उठ गया है। बैंक का यह तर्क पूरी तरह से उचित है कि न केवल वे कर्मचारी जो बेईमान हैं, बल्कि वे कर्मचारी भी जो घोर लापरवाही के दोषी हैं, बैंक की सेवा में बने रहने के योग्य नहीं हैं।

[विशेष ज़ोर दिया गया]

9. आरोप को साबित करने के लिए कई गवाहों की जाँच की गई। उनमें से एक एच.एस. शर्मा थे, जिन्होंने शुरुआती जाँच की थी और जिनके सामने उत्तरदाता ने एक बयान दिया था, जिसमें उसने मोटे तौर पर उन तथ्यों को स्वीकार किया था जो दूसरे आरोप का विषय थे। आई.एम. रावल, जो कैशियर थे, और आई.सी. ओझा, जो कार्यवाहक ब्रांच मैनेजर थे, की भी जाँच की गई। उनके सबूतों के आधार पर, जाँच अधिकारी ने उत्तरदाता को दूसरे आरोप का दोषी पाया, और इस बात को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट ने इस निष्कर्ष में बिना यह साफ़ तौर पर कहे दखल दिया कि यह दोष-निष्कर्ष गलत था। हाई कोर्ट ने इस तरह काम किया, मानो वह विभागीय जाँच के ऊपर अपील सुन रहा हो, और उसने इस अस्पष्ट धारणा के आधार पर निष्कर्ष में दखल दिया कि उत्तरदाता ने "बढ़ते ग्राहक-अनुकूल माहौल" में ज़रूर सद्भावना से काम किया होगा। दोष-निष्कर्ष में दखल देने का डिवीज़न बेंच के पास कोई औचित्य नहीं था।

10. यह तथ्य कि आपराधिक अदालत ने बाद में उत्तरदाता को 'संदेह का लाभ' (benefit of doubt) देते हुए बरी कर दिया, किसी भी तरह से पहले से पूरी हो चुकी अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य नहीं ठहराएगा, और न ही यह

'दोष-सिद्धि' या उसके परिणामस्वरूप दी गई सज़ा की वैधता पर कोई असर डालेगा। चूंकि आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक 'सबूत का मानक' विभागीय जांच में आवश्यक मानक से अलग होता है, इसलिए एक ही तरह के आरोप और सबूत, इन दोनों तरह की कार्यवाहियों में अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं–यानी, विभागीय कार्यवाही में 'दोष-सिद्धि' और आपराधिक कार्यवाही में 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी किया जाना। यह बात तब और भी अधिक लागू होती है, जब आपराधिक कार्यवाही की तुलना में विभागीय कार्यवाही, घटना के समय के लिहाज़ से, घटना के अधिक करीब होती है। आपराधिक अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्षों का, पहले से पूरी हो चुकी 'आंतरिक जांच' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी, जो जांच के निष्कर्षों और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई सज़ा को, उन्हें चुनौती न देकर, 'अंतिम रूप' प्राप्त करने देता है, वह कई वर्षों बाद इस आधार पर उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता कि बाद में आपराधिक अदालत ने उसे बरी कर दिया है।

11. इसलिए, हमारी यह राय है कि हाई कोर्ट का सज़ा को रद्द करना और पिछली तनख्वाह तथा अन्य लाभों के साथ नौकरी पर वापस रखने का निर्देश देना सही नहीं था। असल में, हाई कोर्ट का पिछली तनख्वाह देने का निर्देश उस व्यक्ति को इनाम देने जैसा है, जो दुराचार का दोषी पाया गया है। हालाँकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साबित हुए आरोप में न तो पैसों का गबन शामिल था और न ही कोई धोखाधड़ी वाला आचरण, और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी यह राय है कि नौकरी से निकालने की सज़ा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से बदल दिया जाना चाहिए, जिसमें नौकरी पर वापस रखना शामिल नहीं होता।

38. बैंक कर्मचारी के आचरण पर ज़ोर देते हुए, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने **'डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकारी) एवं अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव'** मामले में, जो **(2021) 2 एससीसी 612** में रिपोर्ट किया गया है, निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

I. 42. <u>निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि बैंकिंग व्यवसाय में, हर बैंक कर्मचारी के लिए पूर्ण समर्पण, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए कर्मचारी को अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के पैसे का लेन-देन करता है; और यदि इसका पालन नहीं किया जाता, तो जनता/जमाकर्ताओं का विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा।</u> इसी अतिरिक्त कारण से, हमारी यह राय है कि हाई कोर्ट ने उत्तरदाता की बर्खास्तगी के उस आदेश

को रद्द करके एक स्पष्ट त्रुटि की है, जो 24-7-1999 को जारी किया गया था और जिसे 15-11-1999 के आदेश द्वारा विभागीय अपील में पुष्ट किया गया था। **[विशेष ज़ोर दिया गया]**

39. मौजूदा मामले में, जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, दोनों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उत्तरदाता पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने भी सबूतों की दोबारा जांच की और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष से सहमति जताई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त आदेश बिना किसी सबूत के आधारित थे, या फिर ठोस और विश्वसनीय सबूतों के अभाव में वे गलत या मनमाने थे। ट्रिब्यूनल ने एक अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर काम किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि इस बात की पूरी संभावना है कि आरोप-पत्र में बताई गई अनियमितताएं मैनेजर द्वारा उत्तरदाता के कहने पर की गई थीं, और वह उस अनियमित ऋण स्वीकृति का सीधा लाभार्थी था, उसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड के आदेश में गैर-कानूनी रूप से हस्तक्षेप किया। ट्रिब्यूनल ने यह टिप्पणी करने में भी गलती की कि उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जो दंड लगाया गया है, वह बहुत कठोर और असंगत है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उसे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।

40. यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि किसी कर्मचारी को सेवा से अनिवार्य रूप से रिटायर करने का मतलब यह नहीं है कि वह रिटायरमेंट के लाभों का हकदार नहीं है; इन लाभों से उसे केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब उसे सेवा से बर्खास्त किया गया हो। दुर्भाग्यवश, हाई कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार किए बिना, और कुछ अप्रासंगिक कारण जोड़ते हुए, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को ही सही ठहरा दिया।

41. ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, हमारा यह मत है कि ट्रिब्यूनल और साथ ही हाई कोर्ट द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता, और इसलिए, उन्हें रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका स्वीकार की जाती है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, चूंकि उत्तरदाता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया है, इसलिए वह कानून के अनुसार ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन संबंधी लाभों का हकदार है।

42. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है।

43. लंबित आवेदन (यदि कोई हों) निपटा दिए जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील निस्तारित।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।